वर्ष : 17 | अंक : 178 | मूल्य : 02 रुपया मात्र | पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित | शनिवार 18 अप्रैल 2026 | लोकतंत्र का स्तंभ

लोकसभा में महिला आरक्षण पर गरमाई बहस सरकार ने 33% आरक्षण कानून किया लागू

आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर दूसरे दिन भी लंबी और तीखी बहस जारी रही। पहले दिन करीब 13 घंटे तक चली चर्चा के बाद गुरुवार को भी सदन में तीन संशोधित विधेयकों पर विचार-विमर्श जारी है, जिनका उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्द लागू करना और सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। यह वही कानून है जिसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। कानून लागू, लेकिन असर बाद में सरकार के इस फैसले के बाद स्थिति यह बनी है कि भले ही वर्तमान में चर्चा में चल रहे संशोधन विधेयक पारित न हों, तब भी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा। कानून के अनुसार, महिला आरक्षण का लाभ तभी लागू होगा जब जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगी, जिसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में मौजूदा अनुमान के मुताबिक, यह आरक्षण 2034 के बाद ही प्रभावी रूप से लागू हो पाएगा।

2029 से लागू करने की कोशिश : सरकार और कुछ दलों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कर दिया जाए। इसके लिए तीन अलग-अलग कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिन पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इन विधेयकों पर शाम करीब 4 बजे मतदान होने की संभावना जताई जा रही है।

विपक्ष ने उठाए सवाल : सरकार द्वारा कानून को तुरंत लागू करने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जब संसद में अभी इस विषय पर संशोधन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, तो ऐसे समय में कानून को लागू करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। हालांकि सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिसूचना जारी कर कानून लागू करने का अधिकार उसके पास है और यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि सरकार कानून के प्रभावी होने की तारीख तय कर सकती है।

महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री की अपील- अंतरात्मा की आवाज सुनकर सर्वसम्मति से पारित कराएं विधेयक

नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़े 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पर शुक्रवार को लोकसभा में शाम 4 बजे मतदान होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों से इस ऐतिहासिक विधेयक के पक्ष में मतदान करने और इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश की नारीशक्ति को सशक्त बनाने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने घर की मां, बहन, बेटी और पत्नी का स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और महिलाओं को नए अवसरों से वंचित न करें। मोदी ने विश्वास जताया कि यदि यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होता है, तो इससे देश की नारीशक्ति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, "आइए, हम मिलकर इतिहास रचें और देश की आधी आबादी को उसका हक दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में इस विधेयक पर व्यापक चर्चा हो चुकी है, जो देर रात तक चली। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सभी आशंकाओं और भ्रमों का तर्कसंगत समाधान किया गया है और सदस्यों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले चार दशकों से राजनीतिक बहस का विषय रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ इस विधेयक के पक्ष में मतदान करें।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने का कारण, सरकार पर बढ़ता दबाव

भारत की राजनीति में वर्तमान समय में तूफान देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार के ऊपर आक्रामक होता चला जा रहा है। वहीं सरकार विपक्ष पर आक्रामक होकर अपना बचाव करने और अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए जिस तेजी के साथ काम कर रही है उसने भारतीय राजनीति में एक नया तूफान ला दिया है। इसी बीच सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर 2029 के लोकसभा चुनाव का बड़ा खेल करना चाहती है। जिस तरह से सरकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए सरकार के लिए जरूरी हो गया था कि वह महिला आरक्षण को लेकर जनगणना के पहले ही परिसीमन के माध्यम से सीटें बढ़ा ले।

परिसीमन आयोग में अपने लोगों की नियुक्ति करके 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले महिला आरक्षण निश्चित कर दे। सरकार ने इसके लिए भी ऐसा समय चुना जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में महिला आरक्षण की दुधारी तलवार चलाना सवाल खड़े कर रही है। सरकार का मानना है, कि इससे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। जब राजनीतिक दल और उनके सांसद चुनाव प्रचार में फंसे होंगे उसी बीच विशेष सत्र बुलाकर संसद से बिल पास कराकर 2029 के लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह तैयार कर लेंगे। परिसीमन का मुद्दा विशेष रुप से संवेदनशील है, क्योंकि परिसीमन आयोग सरकार बनाएगी।

ठीक उसी तरह जिस तरह से चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, विपक्ष की यह आशंका है। यदि सरकार ने परिसीमन आयोग बना लिया, उसमें 2026 में जो जनगणना हो रही है उसको बिल में स्थान नहीं दिया, ऐसी स्थिति में सरकार हिंदी भाषी राज्यों की जहां भाजपा का प्रभाव है वहां अपनी सीटों को बढ़ा लेगी। सरकार यदि यह बिल पास कराने में सफल हो गई तो 2047 तक फिर उसके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाएगी। इस बात को विपक्ष और दक्षिण के राज्य अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 2023 में जब यह महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उस समय विपक्ष ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने सरकार पर दबाव बनाया था। उस समय सरकार ने जनगणना और उसके बाद परिसीमन की बात कहकर आरक्षण को 2029 तक के लिए टाल दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं रहे। उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उसके बाद से सरकार के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। भारत में राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आया है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

एलपीजी के बाद भारत में अब सोने और चांदी किल्लत! बैंकों ने रोका आयात

नई दिल्ली। एलपीजी के बाद देश में सोने और चांदी की भी किल्लत हो सकती है। भारतीय बैंकों ने विदेशी सप्लायर्स से सोने और चांदी के आयात ऑर्डर रोक दिए हैं। कई टन सोना-चांदी कस्टम में अटका है, क्योंकि इनके आयात को अधिकृत करने वाला कोई औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात ट्रेड सूत्रों ने कही है। बिना नए आयात के भारत को सप्लाई से जुड़ी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर भारतीय डिमांड गोल्ड और सिल्वर के ग्लोबल प्राइसेज पर असर डाल सकती है। जबकि यह देश के व्यापार घाटे को कम सकता है और रुपये को सपोर्ट कर सकता है। रुपया, इस साल अब तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियन करेंसीज में से एक है। रुपये पर दबाव घटाने के लिए अथॉरिटीज ने कई कदम उठाए हैं। हाल में रिफाइनरीज से अपने स्पॉट डॉलर परचेज को रोकने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आमतौर पर प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में एक ऑर्डर जारी करता है, जिसमें सोने और चांदी का आयात करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अधिकृत बैंकों की लिस्टिंग करता है।

पंजाब में ईडी ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर व अन्य ठिकानों पर मारे छापे

लुधियान। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ईडी के रडार पर आ गए हैं। शुक्रवार सुबह ईडी की टीमों ने मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। अचानक हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह तड़के ईडी के अधिकारी लुधियाना पहुंचे और संजीव अरोड़ा की कोठी को चारों ओर से घेर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर आवास के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जांच में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन के सौदों में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीमें घर के अंदर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही हैं हालांकि, अभी तक विभाग की ओर से इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि आने वाले घंटों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति बनने पर दी बधाई, अनुभव और कार्यशैली को सराहा

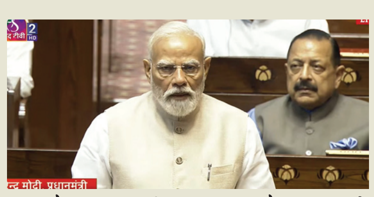

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश के लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी और इसे सदन के गहरे विश्वास का प्रतीक बताया। राज्यसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का पुनर्निर्वाचन उनके अनुभव, संतुलित कार्यशैली और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि उपसभापति के रूप में हरिवंश ने न केवल सदन की कार्यवाही का कुशल संचालन किया है, बल्कि अपने पूर्व अनुभवों से सदन को समृद्ध भी किया है, जिससे सदन का माहौल और अधिक परिपक्व हुआ है। मोदी ने कहा, "राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन का आपके (हरिवंश) प्रति गहरा विश्वास दर्शाता है। साथ ही, बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव से सदन को जो लाभ प्राप्त हुआ है, उसका भी यह प्रमाण है। सदन को साथ लेकर चलने का जो आपका प्रयास रहा है, उस पर सदन ने एक प्रकार से अपनी मोहर लगा दी है। यह वास्तव में आपके अनुभव और योगदान का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनका नया कार्यकाल भी समर्पण, संतुलन और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा और सदन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हरिवंश ने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद अपना अधिकांश समय संसदीय कार्यों को समर्पित किया है और सभापति की अनुपस्थिति में वे कुशलतापूर्वक सदन का संचालन करते रहे हैं।

दिल्ली से लेकर बिहार तक बादलों की हलचल और आंधी-बारिश के संकेत, अलर्ट जारी

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलेगा

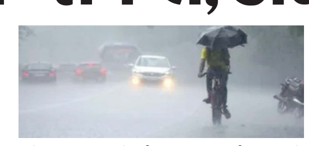

देश में मौसम का मिजाज हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ तेज धूप, चुभती गर्मी और लू का खतरा लोगों को बेहाल कर रहा है तो दूसरी तरफ अचानक बदलता मौसम राहत की उम्मीद भी जगा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक जहां बादलों की हलचल और आंधी-बारिश के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बदलते मौसम ने लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित किया है। सुबह और शाम हल्की राहत मिलती है, लेकिन दोपहर की तपिश लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं और हर क्षेत्र में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिलेगा। कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होगी तो कहीं लू का कहर और ज्यादा तेज हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलेगा, जबकि मैदानी इलाकों में आंशिक राहत के बावजूद गर्मी बनी रहेगी। कई जगहों पर बादलों की आवाजाही से तापमान में हल्की गिरावट आएगी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई रेड जोन में पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए इस हफ्ते में दोहरी मुसीबत पैदा हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री से बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 21 से बढ़कर 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यूपी में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है और हालात धीरे-धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। बांदा जैसे जिलों में तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जो लू की स्थिति को और खतरनाक बना रहा है। दिन के समय तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो गर्मी को और ज्यादा तीखा बना देती हैं। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और बाहर निकलने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

होर्मुज के हालात पर भारत की दो टूक कहा- नाविकों की मौत, जहाजों पर खतरा हमें स्वीकार्य नहीं

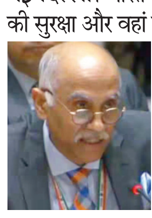

नई दिल्ली। भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मालवाहक जहाजों की सुरक्षा और वहां लगातार बढ़ते तनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में आम नागरिकों की हत्या और व्यापारिक जहाजों पर मंडराता खतरा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय प्रतिनिधि ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने की पुरजोर वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत हरीश पी ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से होने वाला समुद्री व्यापार भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख जताया कि वर्तमान संघर्ष के दौरान व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया गया है। भारतीय राजदूत ने कहा कि इस युद्ध की स्थिति के कारण जहाजों पर कार्यरत कई भारतीय नाविकों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ी है, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है।

जब तक मैं खड़ी हूं, बांग्ला-विरोधी ज़मींदारों को लोगों पर तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी

कोलकाता। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कूच बिहार ज़िले की अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए सीएम ममता ने बंगाल की रक्षा करने, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इसकी धर्मनिरपेक्ष बनावट को बनाए रखने के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं खड़ी हूं, मैं इन बांग्ला-विरोधी ज़मींदारों को इस धरती के लोगों पर कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं बंगाल की रक्षा के लिए लड़ूंगी, उन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखूंगी जिनकी सेवा के लिए मैं चुनी गई हूं, इस खूबसूरत राज्य के भविष्य को सुरक्षित करूंगी, और हमारी धर्मनिरपेक्ष बनावट और समावेशी भावना को हर उस ताकत से बचाऊंगी जो इसे तोड़ने की कोशिश करती रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पोस्ट में कहा कि मुझे आपकी जरूरत अपने पास है, जैसा कि आप हमेशा से रहे हैं। अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि वे अपनी विचारधारा पर हमेशा कायम रही हैं और उन्होंने इस यात्रा का हर कदम लोगों के साथ मिलकर तय किया है।

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में की 865 करोड़ की जब्ती

एजेंसी। नई दिल्ली

चुनाव आयोग की ओर से जारी सख्ती के चलते तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले अब तक कुल 865 करोड़ रुपये की नकदी एवं अवैध सामग्री की जब्ती की जा चुकी है। दोनों राज्यों में 17 अप्रैल तक कुल मिलाकर 99 करोड़ रुपये नकद, 32 लाख लीटर 84 करोड़ रुपये की शराब, 174 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 159 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 350 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मतदान को हिंसा, भय और लालच से मुक्त रखने के लिए कई उपाय किए गये हैं । इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है और शिकायतों को त्वरित निपटान किया जा रहा है। आयोग की ओर से 5011 फ्लाइंग स्क्वायड टीम तैनात की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 शामिल हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों में 5,363 निरीक्षण टीम तैनात की गई है। आयोग के अनुसार 26 फरवरी को चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद 17 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती की गई। पश्चिम बंगाल में 21 करोड़ रुपये नकद, 31 लाख लीटर शराब (81 करोड़ रुपये मूल्य), 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 54 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं तथा 172 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गईं। कुल जब्ती 427 करोड़ रुपये रही। वहीं तमिलनाडु में 78 करोड़ रुपये नकद, 97 हजार लीटर शराब (3 करोड़ रुपये मूल्य), 74 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 105 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं तथा 178 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गईं।

इजराइल और ईरान समर्थक लेबनान के आतंकी संगठन हिज्बुल्लाह के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम

एजेंसी। वाशिंगटन/बेरूत/तेल अवीव

इजराइल और ईरान समर्थक लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम (सीज फायर) हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि लेबनान और इजराइल के राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर अपनी सहमति जता दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''मैंने आज लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। दोनों ही 10 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। दोनों नेताओं ने सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वे पूर्वी समय के अनुसार शाम पांच बजे (भारतीय समयानुसार रात ढाई बजे) औपचारिक रूप से हमले रोक देंगे।" अमेरिका के सीबीएस न्यूज चैनल, लेबनान के लोरिएंट टुडे अखबार और इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेशमंत्री मार्को रूबियो को निर्देश दिया है कि वे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के साथ मिलकर काम करें, ताकि इजराइल और लेबनान को स्थायी शांति हासिल करने में मदद मिल सके। राष्ट्रपति ने कहा कि वे नेतन्याहू और औन को बातचीत के लिए व्हाइट हाउस भी आमंत्रित करेंगे। उल्लेखनीय है कि लेबनान में चल रहा यह संघर्ष इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच है। हिज्बुल्लाह लेबनान में ईरान का छद्म आतंकी संगठन है। लेबनान के राष्ट्रपति औन ने पश्चिम एशिया में संघर्ष-विराम कराने की कोशिशों के लिए ट्रंप का आभार जताया है। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के अनुसार, औन ने कहा कि ट्रंप के प्रयासों से इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने लेबनान के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट के मंत्रियों से कहा कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर लेबनान के साथ युद्ध विराम पर सहमति दी। उन्होंने इस मामले पर औपचारिक वोट कराने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप हमारे दोस्त हैं। इजराइल पूरी तरह उनके साथ है। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि संघर्ष विराम के दौरान रणनीतिक जगहों तैनात हमारे सुरक्षा बल नहीं हटेंगे।

ईरान से भारत ने निकाले 2361 लोग : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान से अपने एवं मित्र देशों के 2361 नागरिकों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से सुरक्षित निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, "संघर्ष के प्रकोप के बाद से हमने 2,361 नागरिकों को ईरान से सुरक्षित रूप से निकालने में मदद की है। इनमें से 2,060 आर्मेनिया के माध्यम से और 301 अज़रबैजान के माध्यम से आए हैं। इन 2,361 लोगों में 1,041 भारतीय छात्रों के साथ-साथ तीन विदेशी भी शामिल हैं। एक बांग्लादेश से, एक श्रीलंका से और एक गुयाना से है। उन्होंने कहा कि ईरान में अभी भी 6000 से 7000 भारतीय मौजूद हैं। पश्चिम एशिया संकट पर एक अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने भी कहा, "सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकास की निगरानी करना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय में एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष परिचालन कर रहा है और हमारे मिशनों के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

खास खबर

नरेला के भोरगढ़ इलाके में फैक्ट्री में आग, 16 दमकल गाड़ियां मौके पर जुटीं

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के नरेला औद्योगिक क्षेत्र के भोरगढ़ इलाके में शुक्रवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और देखते ही देखते दस दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकल विभाग के अनुसार, सुबह करीब 7:45 बजे फैक्ट्री नंबर 214-ए, ए ब्लॉक, नरेला में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआती तौर पर मौके पर पांच गाड़ियों को भेजा गया। आग की गंभीरता को देखते हुए 8:10 बजे इसे 'मेक-4' (बड़ा) घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। दमकल अधिकारी के अनुसार बढ़ती आग को देखते हुए 16 दमकल गाड़ियों को भेजा गया। खबर लिखे जाने तक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

नाबालिग ड्राइवर को दी गई जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने फरवरी में हुए एक सड़क हादसे के नाबालिग आरोपित को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज रजत गोयल ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। याचिका इस हादसे में मृत साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने दायर की है। जिसमें कहा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपित को गैरकानूनी रुप से जमानत दी है। याचिका में कहा गया है कि जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटित अपराध के साक्ष्यों पर पूरे तरीके से गौर नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। आरोपित नाबालिग आदतन अपराधी है। जिस वाहन से हादसा हुआ वो कई घटनाओं में लिप्त रहा है और ओवरस्पीडिंग, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने समेत कई चालान हो चुके हैं। याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 4 फरवरी को जब नाबालिग आरोपित को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया तो उसे किसी की जान जाने का कोई पछतावा नहीं था। उसे 10 फरवरी को जमानत देते समय याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। साहिल की मां ने याचिका में कहा है कि इस तरह की परिस्थिति में उसे लगता है कि आरोपित के पिता और उसके सहयोगी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, 3 फरवरी को साहिल की मौत सड़क हादसे में हुई थी। साहिल बाइक पर था और एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एसयूवी एक नाबालिग चला रहा था। इस हादसे में एक दूसरे कैब ड्राईवर को भी गंभीर चोटें लगी थी।

विधेयक पारित नहीं होने पर घट जाएगा दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्वः निशिकांत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। महिला आरक्षण से जुड़े तीन विधेयकों पर लोकसभा में जारी चर्चा के दौरान शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य निशिकांत दुबे ने कहा कि इस विधेयक के पारित नहीं होने से दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर घट जाएगा। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक के चलते महिलाओं को आरक्षण मिलेगा ही। इसे देने के लिए परिसीमन होगा और जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। ऐसे में कुछ राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और कुछ की घट जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित करने का विधेयक लाई है। अगर यह विधेयक पारित नहीं होता है तो अधिनियम से तहत उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़कर 87 हो जाएंगी और तमिलनाडु की सीटें घटकर 29 हो जाएंगी। दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज ओबीसी के आरक्षण की बात कर रही है लेकिन सोनिया गांधी और स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जातिगत जनगणना कराए जाने से इनकार कर दिया था।

निहाल विहार में विवाद के बाद व्यक्ति की मौत, दो आरोपित हिरासत में

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। बाहरी जिले के निहाल विहार इलाके में मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान के आधार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, डीडीयू अस्पताल से सूचना मिली थी कि निहाल विहार निवासी नारायण वर्मा (50) को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि 16 अप्रैल की रात करीब 11 बजे वीर बाजार चौक के पास नारायण वर्मा का दो लोगों के साथ विवाद हुआ था। बाहरी जिले के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार शव पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले, जिससे मामला शुरू में संदिग्ध बना रहा। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान सामने आया कि विवाद के बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस आधार पर पुलिस ने 17 अप्रैल को निहाल विहार थाने में एफआईआर संख्या 271/26 के तहत धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) में मामला दर्ज कर लिया। मामले में कथित रूप से शामिल दोनों आरोपित भगत सिंह (45) और बाबू सिंह (22) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि विवाद किस वजह से हुआ था और घटना के दौरान क्या परिस्थितियां बनीं। फिलहाल दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है।

मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, हत्या के प्रयास के मामले में थे वांछित

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित हत्या के प्रयास के मामले में वांछित थे और कुख्यात विक्की टक्कर गैंग से जुड़े हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। गिरफ्तार आरोपित जतिन शर्मा (27) महावीर एन्क्लेव का रहने वाला है और उसके खिलाफ चोरी, लूट एवं झपटमारी के 23 मामले दर्ज हैं। वहीं, पवन भंडारी (26) पर भी लूट के चार मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ सेक्टर-23 द्वारका थाने में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल शाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि आठ अप्रैल को डाबड़ी इलाके में महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल पीड़ित बयान देने की स्थिति में नहीं था। इस मामले में 9 अप्रैल को डाबड़ी थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। जांच में जतिन शर्मा और पवन भंडारी का नाम सामने आया, जो इलाके में दहशत फैलाने और दुकानदारों से रंगदारी मांगने में लगे थे। पुलिस उपायुक्त ओ अनुसार 16-17 अप्रैल की रात एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली कि दोनों आरोपित नजफगढ़ की ओर से धूलसिरस चौक के पास आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाया। रात करीब 2:10 बजे स्कूटी पर आते दिखे दोनों आरोपितों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपित जतिन शर्मा द्वारा चलाई गई गोली सिपाही शिवराम की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली जतिन के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद दोनों आरोपितों को मौके से काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और तीन खाली खोखे बरामद किए हैं।

अवैध हथियार गिरोह का किया भंडाफोड़, एक आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से दो पिस्टल, एक देशी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस और 11 खोखे बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान भोला नाथ नगर, शाहदरा निवासीअबू तालिब (27) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपित दिल्ली-एनसीआर में उभरते गैंग का हिस्सा था और बदला लेने के इरादे से हथियार इकट्ठा कर रहा था। पुलिस उपायुक्त के अनुसार क्राइम ब्रांच की ईआर-1 टीम को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि इलाके में जबरन वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को शाहदरा स्थित एक कॉलेज के पास विशेष सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया। सूचना के आधार पर भोला नाथ नगर स्थित ठिकाने पर छापा मारा गया, जहां तलाशी के दौरान आरोपित के कब्जे से दो पिस्टल, एक देशी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस और 11 खाली खोखे बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि उसने ये हथियार उप्र के मेरठ से अलग-अलग सौदों में खरीदे थे। उसने बताया कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी गैंग से बदला लेने की योजना बना रहा था और इसके लिए हथियार जमा कर रहा था। आरोपी ने हथियारों की टेस्ट फायरिंग भी कर रखी थी। पुलिस के अनुसार, अबू तालिब अपने पिता के साथ फल का थोक कारोबार करता है और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसका पहले भी एक आपराधिक मामला दर्ज है, जो फरश बाजार थाने में लंबित है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब हथियार सप्लायर और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

केंद्र से पंजाब, चंडीगढ़ के किसानों को मिली राहत, प्रभावित गेहूं की खरीद नियमों में छूट

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के अनुरोध पर गेहूं खरीद के नियमों में तत्काल प्रभाव से छूट देने की मंजूरी दे दी है, जिससे बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित पंजाब और चंडीगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत है। ये छूट रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2026–27 की शुरुआत से लागू होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को बताया कि 9 अप्रैल को पंजाब सरकार की ओर से प्राप्त अनुरोध के बाद 10 अप्रैल को सभी जिलों में स्थिति का जायजा लेने के लिए टीमें भेजी गईं। जमीनी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने किसानों की मुश्किलों को कम करने और मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पंजाब सरकार के आधिकारिक पत्र के अनुसार सरकार की ओर से दी गई छूट बारिश के कारण चमक खो चुके गेहूं की खरीद सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया, सिकुड़े और टूटे दानें की पहले सीमा 6 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई, क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त दानों की कुल मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट मानदंडों के तहत खरीदे गए गेहूं का अलग से भंडारण किया जाएगा और उसका हिसाब भी अलग रखा जाएगा। इस गेहूं के बिक्री को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पंजाब सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि भंडारण के दौरान गुणवत्ता में होने वाली किसी भी गिरावट और इस छूट से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र के इस फैसले से अब मंडियों में गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित हो सकेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा को ईस्ट विनोद नगर डिपो में आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डीटीसी ईस्ट विनोद नगर डिपो में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इस मौके दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को हरित, स्मार्ट औऱ स्वच्छ बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ोतरी के साथ डीटीसी प्लीट की संख्या बढ़कर लगभग 6300 बसों तक पहुंच गई है। दिल्ली में प्रदूषण-मुक्त सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए आज ईस्ट विनोद नगर डिपो से 200 नई ईवी बसों को दिल्ली की सेवा में समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रही है। दिल्ली में ईवी बसों की संख्या 4500 से अधिक हो चुकी है और 2026 के अंत तक इसे 7000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली से रोहतक रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी चौक से होकर गुजरेगा, जिसमें टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहद, सांपला और रोहतक बस स्टैंड जैसे प्रमुख पड़ाव शामिल है।

लोकसभा में संशोधन विधेयक गिरने पर बोले खरगे- मोदी और शाह अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोकतंत्र को तबाह करने चले थे, उनकी ये साज़िश औंधे मुंह गिरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः कांग्रेस ने लोकसभा में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक के गिरने को मोदी सरकार की "असंवैधानिक चाल" की हार और लोकतंत्र व संविधान की जीत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आधी आबादी को ढाल बनाकर परिसीमन करने की कोशिश की और इस देश के लोकतंत्र, संविधान व संघवाद को चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया। सरकार की ये चालबाज़ी एकजुट विपक्ष-इंडिया ने भांप ली और संविधान संशोधन बिल गिर गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों के नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि मोदी-शाह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने चले थे, उनकी ये साज़िश अब औंधे मुंह गिर गई है। कांग्रेस मोदी सरकार से फिर एक बार मांग करती है कि वो 2023 में पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के चुनावों से ही दिया जाए। कांग्रेस पार्टी सितंबर 2023 से इसकी मांग कर रही है। यह 'नारी शक्ति' के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद शुक्रवार देर शाम संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये महिला बिल नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के राजनीतिक और इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी, संविधान पर आक्रमण था। विपक्ष ने इसे रोक दिया।

वर्क-फ्रॉम-होम और प्रदूषण का डबल अटैक- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहा 'साइलेंट लिवर क्राइसिस'

» हर 5 में 1 भारतीय 'साइलेंट लीवर डिजीज' के खतरे में, दिल्ली में 22.8% आबादी प्रभावित

» "लिवर रोग अब केवल शराब से नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल और प्रदूषण से पैदा हो रहा एक साइलेंट किलर बन चुका है" - डॉ. अपूर्व पांडे

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) संस्कृति, खराब खानपान और बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लिवर रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह एक 'साइलेंट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस' का रूप ले चुके हैं। यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मॉडल टाउन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि लिवर अब केवल शराब के कारण नहीं, बल्कि आधुनिक जीवनशैली और प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से डॉ.अपूर्व पांडे (एडिशनल डायरेक्टर एवं एचओडी – गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एवं हेपेटोलॉजी) और डॉ. शैलेश शर्मा (एचओडी एवं सीनियर कंसल्टेंट – पीडियाट्रिक्स) शामिल रहे। डॉक्टरों के अनुसार, भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति 'साइलेंट लीवर डिजीज' के खतरे की ओर बढ़ रहा है। DiaFib-Liver Study में 9,202 लोगों की स्क्रीनिंग में 5% लोगों में बिना लक्षण वाला सिरोसिस पाया गया। वहीं, MASLD के मामले 2023 के 1.3 बिलियन से बढ़कर 2050 तक 1.8 बिलियन होने का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में स्थिति और भी चिंताजनक है। यहां 22.8% आबादी फैटी लिवर से प्रभावित है, जबकि डायबिटीज और मोटापे वाले हाई-रिस्क ग्रुप में यह आंकड़ा 60.4% तक पहुंच जाता है। एम्स के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में फैटी लिवर के मामले ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग 40% अधिक हैं। डॉ. अपूर्व पांडे ने कहा, "PM2.5 जैसे प्रदूषक सांस के जरिए खून में मिलकर लिवर तक पहुंचते हैं और सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फाइब्रोसिस का कारण बनते हैं। वर्क-फ्रॉम-होम के कारण कम हुई शारीरिक सक्रियता इस खतरे को और बढ़ा रही है।" उन्होंने आगे बताया कि उनके ओपीडी में आने वाले 30 से 40 प्रतिशत मरीज फैटी लिवर के होते हैं, जिनमें अधिकांश की उम्र 20 से 50 वर्ष के बीच होती है। खासतौर पर 20–30 वर्ष के युवा वयस्क और 40–60 वर्ष के लोग इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अंत में डॉक्टरों ने कहा कि लिवर रोग अब 'साइलेंट किलर' बन चुके हैं और समय पर पहचान व जीवनशैली में सुधार ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की छठी पूरक चार्जशीट

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में आरोपित और आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव ऊर्फ कैराके खिलाफ दिल्ली पुलिस की मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है। ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है। कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है। दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है। इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है। कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

ब्रिगेडियर पर हमले के मामले में फरार चार आरोपित गिरफ्तार, इस्तेमाल की गई कार बरामद

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के वसंत एन्क्लेव इलाके में सेना के ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सभी फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहले गिरफ्तार मुख्य आरोपित सतेंद्र के अलावा अब उसके चार अन्य साथियों को भी दबोच लिया गया है। दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सुरजीत सिंह (36), सुनील शर्मा (53), आशीष (32), सभी निवासी मेहरम नगर, दिल्ली और सतेंद्र (35) निवासी भिवानी, हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुरजीत, मुख्य आरोपित सतेंद्र का परिचित है। घटना वाले दिन सभी आरोपित मेहरम नगर में साथ बैठे थे, तभी सतेंद्र का फोन आया, जिसमें वसंत एन्क्लेव में हुए झगड़े की जानकारी दी गई। इसके बाद सभी आरोपित सुरजीत की कार (सफेद रंग की हुंडई ऑरा) में सवार होकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंचने के बाद आरोपितों और ब्रिगेडियर के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित वहां से फरार हो गए और अपने-अपने घरों में छिप गए। मामले के दर्ज होने की जानकारी मिलते ही वे घर छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर अंततः सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना में इस्तेमाल की गई हुंडई ऑरा कार को भी बरामद कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। आरोपितों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

क्या था पूरा मामलाःउल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले वसंत एन्क्लेव इलाके में 11 अप्रैल की रात ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह आरोड़ा और उनके बेटे तेजस पर उस समय हमला कर दिया गया था, जब उन्होंने अपनी रिहायशी इलाके के बाहर खड़ी कार में कुछ लोगों को शराब पीने से रोका था। इसी बात पर आरोपितों ने गुस्से में आकर दोनों के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद मामला काफी चर्चा में रहा और पुलिस पर आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव था। अब सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ा दिया है।

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा, सत्ता पक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द के इस्तेमाल पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई, जिसके चलते सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश की जनता का अपमान है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुनकर इस पद पर बैठाया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए और उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बातें सार्वजनिक मंचों पर कही जाती हैं, उन्हें उसी रूप में संसद में दोहराना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है और इस प्रकार की बयानबाजी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। विवाद के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान का बचाव करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सच्चाई सामने लाने की जरूरत है और सरकार देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा और आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए जा रहे हैं, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

संक्षिप्त समाचार

नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान हामीद इंटर के पास पक्के चबूतरों पर चला बुलडोजर

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हमीद इंटर कॉलेज के आसपास नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानों के आगे बनाए गए पक्के चबूतरों को हटाया गया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और राहगीरों को आने-जाने में सुविधा मिल सके। नगर पालिका की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने दुकानों के सामने बने पक्के चबूतरों को हटाकर सार्वजनिक मार्ग को खाली कराया। कार्रवाई के समय मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और नगर पालिका की इस कार्रवाई की सराहना भी की। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रामपुरः जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश सागर ने एसपी से की मुलाकात अंबेडकर का स्मृति चिन्ह किया भेंट

लोकतंत्र की शान , मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। राष्ट्रीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश सागर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का फोटो स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान संगठन की ओर से सामाजिक समरसता, कानून व्यवस्था एवं जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश सागर ने कहा कि बाबा साहेब के विचार समाज को समानता और न्याय का रास्ता दिखाते हैं, और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर संगठन समाज में जागरूकता का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर नगर क्षेत्राधिकारी (सीओ सिटी) को भी बाबा डॉ भीमराव अंबेडकर की फोटो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।एवं अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग की अपील की। मुलाकात के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

घायल चालक की उपचार के दौरान मौत, परिवार में मचा कोहराम

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव कोकापुर निवासी मनीराम राणा पुत्र रमेश सिंह बुधवार की शाम को सैद नंगली थाना कस्बे से ट्रैक्टर खरीद कर ला रहा था। इस दौरान सकतपुर एवं सैद नंगली के बीच स्थित मार्ग पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया था। जिसके नीचे दबकर चालक मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। जहां सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस ने राहगीरों की मदद से घायल ट्रैक्टर चालक को हसनपुर सीएचसी केंद्र में भर्ती करा दिया था। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। जहां मृतक का उपचार किया जा रहा था वही उपचार के दौरान मृतक ने घायल ने दम तोड़ दिया इसके बाद मृतक का सब गांव लाया गया वहीं सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी के पुत्र देवेंद्र खड़कवंशी ने परिजनों को शांतवना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया वहीं युवक की मौत से परिवार के लोगों में कोहरा मचा हुआ है।

हमले के आरोपीयो पर कार्रवाई को लेकर कोतवाली गेट पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ रंजिशन एक युवक की मोटरसाइकिल में बोलोरो से टक्कर मारकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़ित रघुवीर पुत्र यादराम, निवासी ग्राम रुद्रपुर मजरा कनैटा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। और कोतवाली गेट पर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर मामले में जल्द मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।पीड़ित के अनुसार, 16 अप्रैल की रात वह कमाल पैलेस में एक दावत से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। देर रात करीब 1:40 बजे, जब वह रहरा अड्डे के पास पहुँचा, तो गाँव के ही एक युवक अपने अज्ञात साथी के साथ अपनी बुलेरो कार उसके पीछे लगा दी। आरोप है कि पेट्रोल पंप के पास अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से रघुवीर की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। जब पीड़ित गिर गया, तो आरोपी ने दोबारा कार उस पर चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे उसे पैर और सीने में गंभीर चोटें आईं। शोर मचाने पर राहगीरों को आता देख आरोपी भागने लगे, लेकिन उनकी कार पास के खेतों में फंस गई। सूचना पर पहुँची डायल 112 की टीम ने मौके से लावारिस हालत में बुलेरो कार को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और घायल को मेडिकल के लिए भेजा है। प्रदर्शन करने वालों में जसपाल सिंह, अजय पाल सिंह,अमर सिंह,बीरबल,चंपत,फतेह सिंह,तेजपाल सिंह,वीरपाल,लखीचंद नैनसिंह,देवेंद्र राणा, रविंद्र आदि मौजूद रहे। कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है,जांच पड़ताल की जा रही है। घायल को मेडिकल के लिए भेजा गया है,उसके बाद ही मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

लायंस क्लब रामपुर चिराग इंटरनेशनल टीम की मासिक बैठक

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। चिराग क्लब रामपुर चिराग इंटरनेशनल ने आज अजंता होटल में अपनी मासिक बैठक की और आने वाले सप्ताह में कुष्ठ आश्रम जाकर कपड़े वितरण करने का प्रोग्राम सुनिश्चित किया 1 सारी टीम ने एकजुट होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने मे अपना योगदान सुनिश्चित किया जिसमें डायरेक्टर शारदा नरूला, अंजू चतुर्वेदी,रमा अग्रवाल, यामिनी गुप्ता क्लब एडमिनिस्ट्रेटर एवं संस्थापक सरिता बिश्नोई, सचिव मितलेश राजपूत ,कोषाध्यक्ष लवी सक्सेना, लता भटिया, सचिव संजू जैन,सह कोषाध्यक्ष सुधा अधिकारी, सरोज भाटिया,श्वेता शर्मा, सोनू नरूला ने भी इसमें काफी सहयोग किया 1 काशीराम कॉलोनी में जाकर पूरी टीम ने वहां जरूरतमंदों को गर्म कपड़े शॉल और कंबल वितरण किया साथ ही कच्ची खिचड़ी और मूंगफली और रेवड़ी बाटी गई 1 चिराग क्लब हमेशा से ही इस तरह की सेवा कार्यों में तत्पर रहता है और समय समय पर इस तरह सेवा कार्यों के कैंप लगाए जाते हैं।

जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी : मुख्यमंत्री

» लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने

» मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया भरोसा, हर समस्या का प्रभावी निस्तारण कराएगी सरकार

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, "घबराइए मत। सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी।" शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर समस्या/शिकायत का संज्ञान लिया। फिर, अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

2027 में दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज़ बनकर सत्ता में आएगी एआईएमआईएमः चौधरी मुशीर अली खान

लोक तंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल : जनपद संभल में नगर पालिका अध्यक्ष पति चौधरी मुशीर अली खान ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाते हुए 2027 में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चौधरी मुशीर अली खान ने कहा कि प्रदेश में दलितों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी का संकल्प है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलें और सभी को बराबरी का हक दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज़मीन पर उतरकर हर समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं, संसद में असदुद्दीन ओवैसी हर वर्ग के हक में मजबूती से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर अल्पसंख्यकों, दलितों या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी उनकी आवाज़ बनकर संसद में खड़े होते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। चौधरी मुशीर अली खान ने विश्वास जताया कि यदि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की सरकार बनती है, तो प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाया जाएगा और विकास की गंगा बहाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे हर वर्ग का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। अंत में उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव बदलाव का प्रतीक होगा, जिसमें सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत और न्यायपूर्ण सरकार बनाई जाएगी।

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की मासिक पंचायत ज़िला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार के नेतृत्व मैं ज्ञापन दिया गया

लोक तंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

रामपुर । कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई जिसके बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पर जोरदार नारेबाजी की जिसकी आवाज सुनकर आए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने से जिलाध्यक्ष ने इनकार किया और कहा की हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलवाए हम उनको ज्ञापन देंगे किसानों की किसी भी समस्या कासमाधान नहीं हो रहा है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बन्धित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाअध्यक्ष भानु प्रताप सिंह गंगवार ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा की ज़िला प्रशासन किसानों की समस्याओं को ध्यान दे किसानों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसान खेतों की मेंडो पर बैठ कर बिलख बिलख कर रो रहा है और उन्होंने कहा कि जनपद रामपुर में बेमौसम बारिश से गेहूँ की फसल कई स्थानों पर बर्बाद हुई है। पैदावार क्रतिहाई निकल रही है। जो गेहूँ एक एकडू में बीस से पच्चीस कु० निकलता था वह आज मात्र 10 या 12 कु० तक रह गया है, किसानों को मुआफजा दिया जाये। और कहा की मिलक, बिलासपुर, शाहबाद तहसीलों के अंतर्गत बारदाना नहीं है। यह कहकर गेहूं की खरीद नहीं रहा है। और कहा की किसानों की हालात आज बहुत ही बुरी है उसकी जमीन पर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसान की फसलों के हुए नुकसान को सुनने को तैयार नहीं है। किसानों का कर्जा माफ किया जाये और फसलों का ग्राउंड लेवल पर सर्वे कराया जाए। और कहा जनपद में, अवैध खनन पर कार्यवाही नहीं हो रही है तहसील मिलक मैं खानपुर, चांदपुर नदियों को खोदकर खोखला किया जा रहा है खनन माफियों द्वारा जिसपर अधिकारियों की नजर नहीं जा रही अगर किसान अपने खेत से निजी काम के लिए 1 ट्रॉली भी मिट्टी ले जाता है तो उसपर कारवाही होती है टैक्टर ट्रॉली को सीज किया जाता है। ज़िला अध्यक्ष ने कहा की आज कुछ किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे आने वाली 17 तारीख से रामपुर ज़िले मैं (अराजनैतिक) गुट ज़िले भर आंदोलन शुरू हो रहा है और और रामपुर कलेक्ट्रेट मैं अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है सभी किसान अपनी अपनी तैयारिया अभी से शुरू कर दे किसान बचेगा तो देश बचेगा। इस मौके पर सरदार अवतार सिंह, सुनील मौर्य, नीरज कुमार, बाबर खां, जुनैद खां, अब्दुल रज़्ज़ाक खान, रामपाल पटेल, चौ राजपाल सिंह, सुशील कुमार शर्मा, मुशीब अली खां, रामदास कोहली, विजयपाल कयशप सहित अधिक संख्या में किसान मौजूद रहे।

सीएम योगी के निर्देश पर संभल में बड़ी कार्रवाई, दो गांवों में हटे कब्जे और लैंड बैंक में निरंतर वृद्धि

लोक तंत्र की शान

संभलः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान को तेज करते हुए संभल जिला प्रशासन ने दो गांवों में बड़ी कार्रवाई की। आरक्षित श्रेणी की ग्राम सभा भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और कहीं भी तनाव की स्थिति नहीं बनने दी गई।

बिछौली में आदेश के बाद हटे निर्माण–तहसील संभल के ग्राम विछोली में गाटा संख्या 1240 (खाद के गड्ढे हेतु आरक्षित) और गाटा संख्या 1242 (पशुचर भूमि) पर अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह का निर्माण किया गया था। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया था। आदेश के खिलाफ किसी भी स्तर पर अपील न होने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटवा दिया।

डॉ भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी का हुआ आयोजन, अतिथियो को किया गया सम्मानित

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शुक्रवार को हसनपुर नगर के एक बैंकट हॉल में संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 2026 के तहत विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने दीप प्रज्वलित कर किया, संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर न केवल संविधान निर्माता ही थे बल्कि आधुनिक भारत के शिल्पकार थे उन्होंने समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, इस दौरान विधायक ने विभिन्न अतिथियों को बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी का छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया, इस दौरान अंबेडकर विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य को भी बाबा साहब का छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया गया वहीं चंचल सागर तथा अजय पोल आदि सहित विभिन्न अतिथियों को बाबा साहब का छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया गया, इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी ने संगठन की मजबूती और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, वही अंबेडकर विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य ने भी उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाएं मार्ग "शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो; के मूल मंत्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, इस मौके पर सभी ने बाबा साहब के विचारों से संबंधित शपथ भी ली, इस मौके पर मुख्य रूप से हसनपुर ब्लाक प्रमुख ममता गुर्जर, भाजपा हसनपुर मंडल अध्यक्ष राजू राणा, मयंक अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, ईश्वर चंद्र गुर्जर, कल्याण सिंह सैनी, संजय शर्मा, देवेंद्र खड़कवंशी, हुकुम सिंह खड़कवंशी, हेमराज सैनी, भोजराम खड़कवंशी, ममता शर्मा, आम्रपाली गुर्जर, पोरुष अग्रवाल आदि सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे 1

बरेलीः ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने कलेक्ट्रेट पर बोला धावा, नोएडा-गुरुग्राम के श्रमिकों के दमन के खिलाफ राष्ट्रपति और CM को भेजा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान

Bareilly.Sandeep Chandra Uttar Pradesh बरेली। गुरुवार को ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के बैनर तले श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन qकिया गया। कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए संगठन के पदाधिकारियों ने नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में चल रहे श्रमिक आंदोलनों का समर्थन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। प्रदर्शनकारियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने और जेल में बंद कर्मचारियों की बिना शर्त रिहाई की पुरजोर मांग की है।प्रदर्शन के दौरान बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने ज्ञापनों का वाचन करते हुए सरकार का ध्यान श्रमिकों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में आंदोलनरत श्रमिकों की मांगों को तुरंत स्वीकार किया जाए और उनके विरुद्ध की जा रही दमनकारी कार्रवाई को रोका जाए। फेडरेशन ने राष्ट्रीय स्तर पर समान न्यूनतम वेतन लागू करने, कार्यस्थल पर पुख्ता सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्य के निर्धारित 8 घंटे के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखने पर जोर दिया।श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर मजदूर महंगाई और रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक संस्थानों में उनका शोषण बढ़ रहा है। फेडरेशन ने मांग की है कि अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) के लिए नियमानुसार दो गुना वेतन दिया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में महामंत्री संजीव मेहरोत्रा, डॉ. अंचल अहेरी, ध्यान चंद्र मौर्य, गीता शांत और सलीम अहमद सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों को न्याय नहीं मिला और उनकी बुनियादी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से फैसल, देव सिंह, कैलाश, मोहित देवल, केपी सिंह, राजेश तिवारी, टीडी भास्कर, यशपाल सिंह, राम सेवक और उमेश सहित बड़ी संख्या में यूनियन सदस्य मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

बेल तोड़ने के प्रयास में 12 वर्षीय छात्र की पिटाई, वैशाली में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में बेल तोड़ने के प्रयास में एक 12 वर्षीय छात्र की पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। यह घटना बेलसर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव की है। घायल छात्र की पहचान रेहान अली (12) के रूप में हुई है। आरोप है कि रेहान ने गांव के प्रेम मिश्रा के बेल के पेड़ से ढेला फेंककर फल तोड़ने का प्रयास किया था। आरोप है कि प्रेम मिश्रा और सन्नी मिश्रा ने मिलकर रेहान को पकड़ा और डंडे से उसकी पिटाई की। पिटाई के कारण बच्चा बेहोश हो गया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायल रेहान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की मां रुबैदा खातून ने घर लौटने पर बेटे की हालत देखी और उसे लेकर थाने पहुंचीं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी प्रेम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी सन्नी मिश्रा अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घायल छात्र रेहान अली ने बताया कि प्रेम मिश्रा और उसके परिवार के सन्नी मिश्रा ने मेरी डंडे से पिटाई की है। एक मुझे पकड़े हुए था, दूसरा मुझे पीट रहा था। मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने उसके बेल के पौधे पर बेल तोड़ने के लिए ढेला फेंक दिया था। छात्र के मां जुबैदा खातून ने बताया कि प्रेम मिश्रा दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरा लड़का कल दोपहर बेल के पेड़ पर ढेला फेंक दिया था। इसी बात पर गुस्सा होकर प्रेम मिश्रा और सन्नी मिश्रा ने कुत्ते की तरह दौड़ा-दौड़ाकर डंडे से मेरी बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुझे मेरी बड़ी बेटी ने फोन कर घटना की जानकारी दी। जिसके बाद इलाज के लिए उसे बेलसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लेकिन वहां से सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रेहान के सिर पर चोट है। साथ ही उसके पूरे पीठ पर डंडे के काले-काले निशान है। जिसकी वजह से उसे सोने तक में दिक्कत हो रही है। इलाज कराने के बाद मैं अपने बेटे को लेकर थाने गई। इस पर प्रेम मिश्रा ने मुझे धमकी दी कि केस करोगी तो तुम्हें भी पीटेंगे। रेहान की मां ने बताया कि आरोपी का भाई फौज में है, जिसको लेकर वो धमकी देता है कि जब मन करेगा तब तुम्हें पीटेंगे।

मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में महिला टीचर की मौत, स्कूटी से जा रही थी स्कूल, अज्ञात वाहन ने रौंदा

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल जा रही महिला टीचर की मौत हो गई। मृतका की पहचान शिक्षिका बबीता कुमारी (41) के तौर पर हुई है। के अकुराहा खरगी मध्य विद्यालय में पोस्टिंग थी। घटना कांटी थाना क्षेत्र के एनएच-27 स्थित नेता चौक के पास की है। जानकारी के मुताबिक हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतका के पति मुन्ना कुमार जमालपुर रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनके दो पुत्र हैं। बबीता कुमारी मूल रूप से ढेवहा गांव की रहने वाली थी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित किराए के मकान में रह रही थीं। साल 2005 में उनकी नियुक्ति हुई थी। भाई आकाश कुमार ने बताया कि उनकी बड़ी बहन रोजाना स्कूटी से स्कूल जाती थी। रास्ते में अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। जिससे उनकी जान चली गई। वहीं, स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि बबीता कुमारी एक सरल और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका थीं, जिनकी असमय मौत से विद्यालय परिवार स्तब्ध है। इधर, कांटी थानाध्यक्ष रविकांत पाठक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में छापेमारी, पुलिस टीम ने चप्पे-चप्पे को खंगाला, बैरक-टॉयलेट में तलाशी

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पुलिस एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार सुबह नालंदा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद समेत कई जिलों के मंडल कारा में छापेमारी की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य की जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में शुक्रवार सुबह जिलाधिकारी (DM) सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। यह तलाशी अभियान सुबह करीब 4:30 बजे शुरू हुआ। डीएम और एसएसपी के साथ दर्जनों थानों की पुलिस और पुलिस लाइन के बड़ी संख्या में जवानों ने जेल परिसर को चारों ओर से घेर लिया। अधिकारियों ने जेल के सभी वार्डों की बारीकी से जांच की। सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल में बंद कई कुख्यात अपराधियों के हाई सिक्योरिटी वार्ड पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस टीम ने कैदियों के बिस्तरों, शौचालयों और वार्ड के हर कोने की तलाशी ली। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेल के भीतर से संचालित होने वाले संभावित आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना और मोबाइल फोन, सिम कार्ड या मादक पदार्थों जैसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद करना था। करीब 3 घंटे चली इस सघन तलाशी के बावजूद जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित सुरक्षा समीक्षा और पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत की गई थी। जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी एसडीपीओ और कई थानों की पुलिस के साथ-साथ पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। SSP ने बताया कि करीब 3 घंटे तक चली इस सघन तलाशी के बावजूद जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। उन्होंने जेल प्रशासन के सहयोग की भी सराहना की और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे।

मुजफ्फरपुर में गोल्ड कारोबारी की कार बरामद, देर रात हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटी थी

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूट के कुछ ही घंटों के बाद गोल्ड कारोबारी की कार बरामद कर ली है। पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर रही है। बोचहां मार्केट में आभूषण की दुकान चलाने वाले शेखर कुमार गुरुवार रात दुकान बंद करके 10 साल के भांजे के साथ घर लौट रहे थे। उनसर काली चौक के पास सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने टॉर्च जलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। शेखर को लगा कि पुलिस चेकिंग चल रही है। जैसे ही उन्होंने कार रोकी, अपराधियों ने खिड़की के पास पहुंचकर कनपटी पर पिस्तौल सटा दी। बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी से नीचे उतार दिया। इसके बाद कार लेकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर और एसडीपीओ पूर्वी-1 अलय वत्स को सौंपा गया। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की नाकेबंदी की। तकनीकी सर्विलांस की मदद से लूटी गई कार की लोकेशन और अपराधियों के भागने के रास्ते को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस के पकड़े जाने के डर से अपराधी लूटी गई कार को गायघाट थाना क्षेत्र के मुनि कल्याण टोला के पास छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं, इस संबंध में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर लूटी गई कार को बरामद कर लिया है। इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है।

पटना में बड़े भाई ने छोटे को चाकू से गोदा, आरोपी फरार

पत्नी से अवैध संबंध के शक में की हत्या, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर दनियालपुर गांव में एक बड़े भाई ने पत्नी ,से अवैध संबंध के शक में अपने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। यह घटना गुरुवार रात को हुई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय शैलेश रविदास के रूप में हुई है, जो सजिंद्र रविदास का पुत्र था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

शैलेश का भाभी के साथ अफेयर का आरोपः परिजनों के अनुसार, शैलेश का अपनी ही भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग दो महीने पहले शैलेश अपनी भाभी को लेकर घर से फरार हो गया था, जिसके बाद से बड़ा भाई शत्रुघ्न रविदास कथित तौर पर गुस्से में था।

दिल्ली से लौटा, शादी में हुआ विवादः शैलेश दिल्ली में मजदूरी करता था। वह गुरुवार को गांव में पड़ोस के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से लौटा था। रात के समय जब घर के लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, तभी दोनों भाइयों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो गई।

चाकू से कई वार, आंतें तक बाहर निकलींः प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक की मां के मुताबिक, बहस के दौरान बड़ा भाई शत्रुघ्न ने धारदार चाकू से शैलेश के पेट पर कई वार किए। हमले में शैलेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी आंतें बाहर आ गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई घटनास्थल से भाग गया।

PMCH में इलाज के दौरान मौतः परिजनों ने गंभीर रूप से घायल शैलेश को तुरंत पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गहरे घावों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस कर रही छापेमारीः घटना की सूचना मिलते ही खुसरूपुर पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी मृतक का सगा बड़ा भाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फरार आरोपी शत्रुघ्न की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

जनता से संवाद कार्यक्रम में 31 आवेदनों की सुनवाई, समयबद्ध निष्पादन के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिले में सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत 'सबका सम्मान-जीवन आसान' (Ease of Living) कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जनता से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम में कुल 31 आवेदनों पर समेकित रूप से सुनवाई की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों में वर्णित समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर अंचलाधिकारी महिषी, पतरघट, सौर बाजार, सत्तर कटैया सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित आवेदकों में सहुरिया पूर्वी, सौर बाजार निवासी सीताराम आजाद, सहरसा वार्ड संख्या 06 के महेंद्र झा, सत्तर कटैया के कन्हैया कुमार पाण्डेय तथा बरियाही के गोविंद कुमार सहित अन्य लोगों ने राजस्व, भूमि विवाद, आपसी विवाद समेत विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने सभी मामलों के सम्यक निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी कहरा, सत्तर कटैया, सलखुआ, सौर बाजार, नवहट्टा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता (वि. जांच) श्री गणेश कुमार, जिला जनशिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह निदेशक एनईपी श्री पुलक कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार में सुबह-सुबह कई जेलों में एक साथ छापेमारी

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही शासन और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जेलों में एक साथ सघन तलाशी अभियान (सर्च ऑपरेशन) चलाया गया। उत्तर बिहार की सबसे महत्वपूर्ण जेलों में शुमार मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जिले के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी करने पहुंचे।

तड़के 4:30 बजे शुरू हुआ ऑपरेशनः जेल में यह छापेमारी अहले सुबह करीब 4:30 बजे शुरू हुई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों थानों की पुलिस और भारी संख्या में पुलिस लाइन के जवानों ने जेल परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल प्रशासन और कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने एक-एक कर जेल के सभी वार्डों की बारीकी से तलाशी ली।

ज्ञान भारतम मिशन के तहत सहरसा में 480 पांडुलिपियां चिन्हित, संरक्षण व डिजिटलीकरण का कार्य जारी

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत सहरसा जिले में पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब तक किए गए पांच सर्वेक्षणों के आधार पर जिले में कुल 480 पांडुलिपियों की पहचान की गई है। इस उपलब्धि के साथ सहरसा जिला राज्य स्तर पर 14वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में देश की समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक विरासत को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के तहत देशभर में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह अमूल्य धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके। जिले में इस मिशन के अंतर्गत सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों, मठों, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षित पांडुलिपियों की पहचान, सर्वेक्षण, कैटलॉगिंग और डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है। कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र एवं कपड़े पर लिखी गई प्राचीन पांडुलिपियों को विशेष रूप से चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी में पांडुलिपियों के संग्रहण और संरक्षण का कार्य लगातार प्रगति पर है। प्रशासन ने जिले के ऐसे सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपील की है, जिनके पास 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, वे जनहित में इसकी सूचना जिला जनसंपर्क कार्यालय को कार्यालय अवधि में अथवा मोबाइल नंबर 7782859647 पर दें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करने वालों की सराहना की जाएगी। इस पहल से न केवल जिले की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के नए द्वार भी खुलेंगे।

बैंक ऋण योजनाओं की समीक्षा में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी सख्त, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जिला उद्योग केंद्र, सहरसा में शुक्रवार को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से संचालित ऋण आधारित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अपेक्षित उपलब्धि नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित बैंकों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र श्री मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएमएफएमई योजना के तहत निर्धारित 157 लक्ष्यों के विरुद्ध 135 मामलों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन केवल 92 मामलों में ही भुगतान हो पाया है। वहीं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 69 लक्ष्यों के मुकाबले 74 मामलों को स्वीकृति मिली, जिनमें से मात्र 34 मामलों में ही भुगतान किया जा सका है। इस प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों और स्वीकृत मामलों में भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और "एक जिला एक उत्पाद" योजना के तहत मखाना सहित कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनके सफल क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया कि वे सभी आवेदनों पर उदारतापूर्वक और नियमों के अनुरूप विचार करते हुए त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार ने भी बैंकों को अनावश्यक रूप से आवेदनों को अस्वीकृत करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की समुचित जांच कर ही निर्णय लिया जाए। अंत में महाप्रबंधक ने सभी बैंकों से अपील की कि स्वीकृत लंबित मामलों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए अभी से कार्य योजना बनाकर काम शुरू करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, परियोजना प्रबंधक, अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि तथा उद्योग विस्तार पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ऊर्जा स्टेडियम पटना के पास युवक की मौत पर सस्पेंस

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को ऊर्जा स्टेडियम के पास नाले किनारे मिले युवक के शव मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पहचान दीघा कुर्जी बालू पर निवासी राजेश राय के रूप में हुई है। मामले में पत्नी ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस को अब तक हत्या के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

मृतक की पत्नी अनीता कुमारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके पति की साजिश के तहत हत्या की गई है। उन्होंने ससुर सुरेश गोप, देवर और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संपत्ति विवाद को लेकर राजेश को शास्त्री नगर बुलाकर मार डाला गया और शव नाले के पास फेंक दिया गया। अनीता का कहना है कि करीब 10 दिन पहले भी जमीन को लेकर मारपीट हुई थी और जबरन राजेश के हिस्से की जमीन अपने नाम लिखवाने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुर और देवर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मामले में एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि, परिजनों के आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि युवक खुद ई-रिक्शा चलाकर वहां आया और नाले के पास गिर गया, जिसके बाद वह नहीं उठा।

पत्नी ने ससुर-देवर पर लगाया हत्या का आरोप, बोली-जमीन अपने नाम लिखवाने बनाया था दबाव

दक्षिण बिहार में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ साउथ बिहार और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं, दूसरी ओर सीमांचल में बारिश और वज्रपात के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 18 अप्रैल को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। डेहरी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले के राजधानी का पारा 38.9 डिग्री था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार में यह बदलाव अलग-अलग मौसम प्रणालियों की वजह से हो रहा है। उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जा रही है।

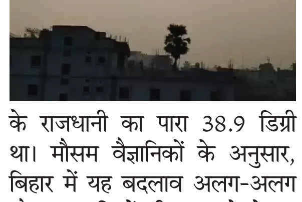

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशाः अर्चना आनंद

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता, सहरसा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सहरसा संयोजक अर्चना आनंद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताते हुए कहा कि यह कदम देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अर्चना आनंद ने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा तथा देश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मूल मंत्र के तहत महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता दी जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संकल्प का मजबूत प्रमाण है, जो आने वाले समय में महिला नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाएगा। अर्चना आनंद ने विश्वास जताया कि यह अधिनियम देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी सुनिश्चित करेगा और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। अंत में उन्होंने इस पहल के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कानून महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

संक्षिप्त समाचार

जींद : वैशाख अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया पिंडारा तीर्थ पर पिंडदान

लोकतंत्र की शान , जींद। पांडु पिंडारा स्थित पिंडतारक तीर्थ पर शुक्रवार को वैशाख अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया तथा पिंडदान कर पितृ तर्पण किया और सुखद भविष्य की कामना की। ऐतिहासिक पिंडतारक तीर्थ पर गुरूवार शाम से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। गुरूवार की पूरी रात धर्मशालाओं में सत्संग तथा कीर्तन आदि का आयोजन चलता रहा। शुक्रवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान तथा पिंडदान शुरू कर दिया जो मध्यान्ह के बाद तक चलता रहा। इस मौके पर दूर दराज से आएं श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया तथा सूर्यदेव को जलार्पण करके सुख समृद्धि की कामना की। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहां पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहां पिंडदान करने के लिए विभिन्न प्रांतों के लोग श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं ने यहां खरीददारी भी की। जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि वैशाख अमावस्या पर दक्षिण भारत में शनि जयंती मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध कर्म, विष्णु और शनि देव की पूजा का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है।

सोनीपत : फार्म हाउस में संचालक और महिला फंदे पर लटके मिले

लोकतंत्र की शान , सोनीपत। सोनीपत के राठधाना रोड स्थित मुनमुन फार्म हाउस में शुक्रवार सुबह संचालक और एक महिला के शव गेस्ट रूम में फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतारकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, जबकि महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान फार्म हाउस संचालक सुमेश स्वामी (45) और दिलशान (35) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी तब मिली जब सुबह संचालक के बेटे मोहित ने फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद वह फार्म हाउस पहुंचा। काफी आवाज लगाने पर भी जवाब नहीं मिला तो उसने कमरे चेक किए। गेस्ट रूम में पहुंचने पर दोनों फंदे से लटके मिले। बेटे के अनुसार, उसने दोनों को बचाने की कोशिश में फंदे को आग लगाई, जिससे फंदा टूट गया और दोनों नीचे गिर गए। उस समय तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सबूत जुटाए। जांच में सामने आया है कि गांव बैयापुर निवासी मोनू फार्म हाउस में टेंपो चलाता है। उसकी पत्नी दिलशान शादी-विवाह कार्यक्रमों में कैटरिंग का काम करती थी और कभी-कभी फार्म हाउस में भी काम करने आती थी। इसी दौरान उसकी पहचान संचालक से हुई थी। पुलिस दोनों के बीच करीबी संबंधों की भी जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मौके से शराब की बोतल, सिगरेट और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। एसीपी मलकीत के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, घटनास्थल की जांच की गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

भोड़की गांव में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल

लोकतंत्र की शान , झुंझुन। झुंझुनू जिले के भोड़की गांव में शुक्रवार सुबह प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सुबह करीब 6 बजे गांव के दिनेश कुमावत ने शौच के लिए जोहड़े में जाने पर शवों को देखा। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ने कीकर के पेड़ पर दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या की है। घटनास्थल पर सल्फास की गोलियां भी मिली हैं जिससे जहर सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस ने युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान भिवानी निवासी 32 साल के सुनील कुमार के रूप में की। युवती की पहचान खींवासर गांव निवासी इंदुबाला के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर गुढ़ागौड़जी सीएचसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि सुनील भारतीय सेना में कार्यरत था और लगभग एक सप्ताह पहले छुट्टी पर घर आया था। उसकी इंदुबाला से दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। परिजनों ने बताया कि सुनील को इंदुबाला से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया था जिसके बाद परिवार में विवाद हुआ। गुरुवार शाम करीब पांच बजे सुनील घर से निकला और उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

डॉ. शालिनी शुक्ला ने बीएएमएस में किया टॉप

» उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया सम्मानित

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले की चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम बड़ोखर की निवासी प्रतिभाशाली छात्रा डॉ. शालिनी शुक्ला ने बीएएमएस की डिग्री उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूर्ण कर अपने परिवार एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा से वर्ष 2019 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। बता दें कि डॉ. शालिनी शुक्ला, स्वर्गीय अनुसुइया प्रसाद शुक्ला की पौत्री एवं पत्रकार अनुराग दीप शुक्ला तथा शिक्षिका श्रीमती पूनम शुक्ला की सुपुत्री हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। डॉ. शालिनी शुक्ला बचपन से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विंध्य एकेडमी, परसवार चुरहट से प्राप्त की। उनके छोटे भाई डॉ. संजीव शुक्ला भी प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के बल पर उन्होंने यह महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। शालिनी की इस उपलब्धि पर बड़े भाई शैलेंद्र पांडेय सहित परिवार के सदस्य नाना रमेश पांडे, नानी श्रीमती दुर्गा पांडे, दादी प्रेमवती, मामा-मामी, मौसी, बुआ एवं फूफा तथा समस्त गुरुजनों और इष्ट मित्रों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. शालिनी शुक्ला ने कहा कि वे सदैव सेवा भाव से कार्य करेंगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी।

बिना अनुमति बोरिंग पर मशीन जब्त

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

» एजेंट सहित जिम्मेदारों पर हुई कार्रवाई
» सेमरिया थाने में खड़ी कराई गई बोरिंग मशीन

सीधी । जिले के चुरहट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुसमहर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन को जब्त कर लिया। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे बिना अनुमति के बोरिंग का कार्य किया जा रहा था। यह कार्य गांव के प्राथमिक स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी पर संचालित हो रहा था, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ था। जानकारी मिलते ही एसडीएम विकास कुमार आनंद ने तत्काल संज्ञान लिया और तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष कुमार मिश्रा को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने बोरिंग कार्य करवा रहे लोगों से दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई भी वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जांच में सामने आया कि जिस स्थान पर बोरिंग हो रही थी, वह जमीन लक्ष्मीकांत प्रजापति की है, जबकि बोरिंग कार्य कराने का जिम्मा एजेंट जितेंद्र चतुर्वेदी के पास था। दोनों ही पक्षों द्वारा आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे यह कार्य पूरी तरह अवैध पाया गया।

भीषण गर्मी के चलते स्कूल समय में बदलाव,सुबह 7:30 से दोपहर 12.30बजे तक संचालित होंगी कक्षाएं

कलेक्टर श्री तिवारी ने जारी किया आदेश

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। जिले में लगातार बढ़ते तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं सीबीएसई शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए शाला संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। अब आगामी आदेश तक सभी विद्यालयों में कक्षाएं प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं शैक्षणिक स्टाफ को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा, ताकि अन्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संपादित किए जा सकें। परीक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही किया जाएगा। इसके साथ ही मूल्यांकन कार्य भी अपने निर्धारित समय पर यथावत जारी रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जो 30अप्रैल तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल प्रबंधकों और संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिल सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो सकें।

जर्जर मकान में रहने को मजबूर अभय का परिवार

» अभय को हाईस्कूल परीक्षा में मिला है प्रदेश में दूसरा स्थान

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को समय पर नहीं मिल रहा है, इस कारण लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत चकडौर निवासी माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम में कक्षा 10वीं में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 के छात्र मध्यप्रदेश में द्वितीय एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभय गुप्ता के पिता कैलाश गुप्ता ने करीब दो साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरपंच सचिव से मांग की लेकिन दो साल बीतने के बावजूद मकान निर्माण के लिए सरकारी अनुदान की मंजूरी नहीं मिल पाई है, खड्डी अंचल के युवा समाजसेवी विनय पांडेय अंकुश मोहनी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया की अभय गुप्ता का परिवार वर्तमान में जर्जर हो चुके कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर है, जहां हमेशा असुरक्षा का खौफ बना रहता है, अभय के पिता कैलाश ने कहा कि दो साल पहले मकान के लिए पंचायत में मांग किया था, लेकिन अब तक पक्के मकान का सपना पूरा नहीं हुआ ऐसे में अभय का परिवार कई बार पंचायत कार्यालय के चक्कर काट चुका है, जहां उसे शीघ्र पक्के मकान का लाभ मिलने के आश्वासन मिलते रहे हैं कच्चे मकान की छत की लकड़ी सड़ चुकी है, दिवाल भी टूटी हुई हैं, इस कारण जहां छत गिरने का खतरा बना हुआ है, बारिश में छत से पानी टपकता रहता था इससे अभय का परिवार चिता में है, यदि समय रहते मकान की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, श्री पांडेय ने जिला प्रशासन से अति शीघ्र प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।

जिला पंचायत सभाग्रह में "नारी शक्ति सम्मान" कार्यक्रम का किया गया आयोजन

» कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची में शामिल 5 छात्राओं को किया गया सम्मानित

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी: "नारी शक्ति वंदन" पखवाडा अंतर्गत शुक्रवार को जिला पंचायत सभाग्रह में "नारी शक्ति सम्मान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि विधायक मुड़वारा संदीप जयसवाल, मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रमेश महरा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कविता पंकज राय, सुश्री माला मौसी, श्रीमती सपना सरावगी, अतिरिक्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग मोदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुडवारा प्रदीप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री वनश्री कुर्वेती परियोजना अधिकारी श्री सतीश पटेल, श्री इंद्रा कुमार साहू, श्रीमती विद्या पाण्डेय, श्रीमती आरती यादव, श्रीमती अनुपना आटे, श्रीमती सुलोचना महोबिया एवं 100 महिलाए उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल में कक्षा 10वीं वर्ष 2026 के परिणामो में जिले अंतर्गत प्रवीण्य सूची में प्रथम 5 स्थान अर्जित करने वाली 5 छात्राए कु. प्रतिभा कुमारी, कु स्वेता पाण्डेय, कु. खुशबु लोधी, कु. शिवानी एवं कु. तनवी गुप्ता को विधायक एवं अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया एवं सुबुध महिलाओ को सम्मानित किया गया।

नवल हार्ट इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल कटनी-छात्रा को नारी शक्ति बंधन फगवाड़ा के तहत सभागार में सम्मानित किया-आज कटनी जिले के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट के जिला पंचायत सभागार में नोबल हार्ट पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल छात्रा श्वेता पांडे के द्वारा कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त कर कटनी जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करने वाली छात्रा श्वेता पांडे का सम्मान विधायक संदीप जयसवाल जी के द्वारा किया गया इस अवसर पर नोवल हार्ड पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर अनिल गर्ग एवं प्राचार्य रचना गर्ग भी कार्यक्रम में उपस्थित थी कटनी जिले में नोबल हार्ट की की छात्रा जिले में सेकंड रैंक 97.6% टॉप पोजीशन में आई जिले के लिए गर्व की बात है।

डंपर-कार टक्कर में डॉक्टर की मौत, साथी गंभीर घायल

लोकतंत्र की शान

पाली। पाली शहर के टीपी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नया गांव रोड स्थित गुर्जर छात्रावास के पास रात करीब एक बजे हुआ। पुलिस के अनुसार कार के साथ चल रहे डंपर ने अचानक मोड़ ले लिया, जिससे कार चालक संभल नहीं सका और तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हादसे में कार चला रहे डॉ. शैलेष विश्नोई (34) निवासी दांता (सांचौर, जालोर) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके साथ सवार डॉ. गौरव सिंह (30) निवासी धिंगाणा (पाली) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल डॉक्टर को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दोनों डॉक्टर नया गांव रोड स्थित जन हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे और अस्पताल के पास ही किराए के मकान में रहते थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन पाली पहुंच गए। डॉ. शैलेष विश्नोई ने वर्ष 2020-21 में नेपाल से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की थी और पिछले चार वर्षों से पाली में कार्यरत थे। उन्होंने पहले बांगड़ हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दीं और करीब छह महीने पहले जन हॉस्पिटल जॉइन किया था। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एएसआई ओमप्रकाश चौधरी के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और फरार डंपर चालक की तलाश जारी है।

वन्य जीव गणना एक मई को, पहली बार युवतियों और महिलाओं को शामिल करेगा वन विभाग, देंगे प्रशिक्षण

लोकतंत्र की शान

चित्तौड़गढ़। जिले में हर वर्ष की तरह इस बार भी वन्य जीव गणना का आयोजन किया जाएगा 1 मई को पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होकर, दो मई सुबह तक चलेगा। जिले में यह गणना बस्सी सेंचुरी और सीता माता अभ्यारण्य के चिन्हित वाटर हॉल्स पर की जाएगी। इस बार वन विभाग नवाचार कर रहा है तथा महिलाएं व युवतियों को भी वन्य जीव गणना में मौका मिलेगा। वन्य जीव संरक्षण में रुचि रखने वाली महिलाएं व युवतियां इसके लिए संपर्क कर सकती है। इसके अलावा सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बुलाया जाएगा। उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मृदुला सिंह ने बताया कि इस बार की वन्यजीव गणना को और अधिक सहभागी और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए विशेष नवाचार किए जा रहे हैं। कॉलेज और स्कूल के वन्य जीव प्रेमी छात्र-छात्राओं को भी इसमें शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्हें वन्य जीव गणना की प्रक्रिया और उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगा। वे इस अनुभव से अधिकतम सीख सकें। इस बार की सबसे खास पहल यह है कि बालिकाओं को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। मृदुला सिंह ने कहा कि कई बालिकाओं में वन्य जीवों को करीब से जानने और समझने की उत्सुकता होती है। ऐसे में उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला वनकर्मियों की टीम उनके साथ रहेगी। उन्होंने इसे बालिकाओं के लिए वन्य जीवों के बारे में सीखने और प्रकृति से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। उप वन संरक्षक ने साथ ही वन्य जीव प्रेमियों, सामाजिक संस्थाओं और आमजन से भी इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया गया है, जिससे वन संरक्षण के प्रति जागरूकता को और मजबूत किया जा सके।

ट्रेप कैमरों में मूवमेंट ज्यादा, चिन्हित किए जा रहे वॉटर हॉल:उप वन संरक्षक वन्य जीव मृदुला सिंह ने बताया कि जिले के बस्सी एवं सीतामाता सेंचुरी में अब तक वन्य जीव गणना होती आई है। लेकिन इस बार वन्य जीव गणना के लिए पैटर्न बदला गया है। गत दिनों दोनों सेंचुरी में कैमरे लगाए गए थे। इन ट्रेप केमरे में जहां वन्य जीवों का मूवमेंट अधिक है उन क्षेत्रों में वाटर हॉल को चिन्हित किया जाएगा। वैसे तो पूरे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास होगा। नियमानुसार प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक वाटर हॉल होता है।

पत्नी गई मायके तो पति ने किया हाइवोल्टेज ड्रामा

» स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके से पहुंची कोतवाली पुलिस
» डायल 112 की समझाइश के बाद नीचे उतर युवक

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। शहर में शुक्रवार दोपहर एक हाइवोल्टेज ड्रामा देखना को मिला है, एक युवक ने टॉवर में चढ़ कर पत्नी को वापस लाने की गुहार लगा रहा था, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी अनुसार शहर के स्थानीय कोटहा निवासी दीपू रावत पिता खेलावन रावत 21 वर्ष अपनी पत्नी के मायके चले जाने से नाराज हो कर लालता चौक के समीप संचालित एसबीआई सीटी ब्रांच के ऊपर लगे वाई फाई टॉवर में चढ़ गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने डायल 112 को मौके पर भेजा, जहां काफी समझाइश के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा गया। दीपू रावत के अनुसार उसका विवाह 2 वर्ष पूर्व मोहल्ले की राधा रावत की लड़की अजू रावत के साथ हुआ था। शादी के बाद में अपनी पत्नी के साथ बाहर कमाने चला गया था। फिर दिनांक 24 मार्च को को वापस पत्नी के साथ सीधी आया। मेरी सास राधा एवं मेरी पत्नी अन्जू का चाचा मेरी पत्नी को पकडकर अपने साथ ग्राम कन्धवार रामपुर नैकिन ले गये, फिर मै 30 मार्च को लेने गया तो नहीं भेजे मुझे भगा दिये है, मेरी पानी गर्भवती है। उसका स्वास्थ भी सही नही रहता है। इसी बात से नाराज हो कर वह आत्महत्या करने के इरादे से टॉवर में चढ़ गया था। कोतवाली पुलिस ने युवक की शिकायत पर पत्नी को शीघ्र वापस लाने का भरोसा दिलाया है।

संक्षिप्त समाचार

एटीएस ने नासिक टीसीएस कंपनी के कथित धर्मपरिवर्तन और यौन शोषण मामले में दो आरोपितों से शुरु की पूछताछ

मुंबई। महाराष्ट्र एंटी टेरोरिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की टीम ने शुक्रवार को नासिक टीसीएस कंपनी में हुए कथित धर्मपरिवर्तन और यौन शोषण मामले की जांच के लिए दो आरोपितों से पूछताछ शुरु कर दी है। इस मामले की मुख्य आरोपित निदा मोईन नाविद खान की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस घटना की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की छानबीन महाराष्ट्र एटीएस ने आज से शुरु कर दी है। इसके चलते आज एटीएस की टीम ने इस मामले के आरोपित समी शेख और रजा मेमन को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। इन दोनों से एटीएस की टीम धर्म परिवर्तन, यौन शोषण के साथ टेरर फंडिंग के ऐंगल से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी आज देश की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की टीम और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी लिया है। इस मामले में धर्मपरिवर्तन का मुद्दा आने से राज्य और देश की जांच एजेंसियां मामले की गहन छानबीन कर रही हैं। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक कुल ८ आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपित निदा मोईन नाविद खान अभी तक फरार है। निदा खान को ढ़ूंढने के आज एसआईटी और एटीएस की टीम ठाणे जिले के भिवंडी और मुंब्रा इलाके में कई जगहों में छापामार कार्रवाई की, लेकिन कहीं भी निदा खान का पता नहीं चल सका है। इस मामले में पुलिस ने निदा के पति मोईन खान से भी कड़ी पूछताछ की है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। निदा खान के मोबाइल लोकेशन से जांच कर रही एसआईटी को पता चला है कि आज ही निदा मुंब्रा इलाके में तीन बार अपनी जगहें बदल चुकी हैं। निदा खान के पति ने पूछताछ में बताया कि उनकी पत्नी फिलहाल गर्भवती है और उसने वकील बाबा सिद्दीकी के माध्यम से नासिक जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस आवेदन पर कल शनिवार को सुनवाई होगी। साथ ही टीसीएस कंपनी ने इस मामले में निदा खान को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि फिलहाल कंपनी के अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रामहोम की अनुमति दी गई है, लेकिन निदा खान को इसकी भी अनुमति न देते हुए सीधे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिलहाल इस मामले की हर ऐंगल से जांच जारी है।

ट्रेड यूनियनों की नेपाल सरकार को चेतावनी, मजदूरों के अधिकार न छीनने के दिए सुझाव

काठमांडू। नेपाल की ट्रेड यूनियनों ने सरकार को अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों को न छीनने की चेतावनी दी है। साथ ही, संघीय सिविल सेवा कानून में किन-किन विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, इस बारे में भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियनों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध और हस्तक्षेप को बंद करने की मांग की है। दरअसल, मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक दलों से आबद्ध ट्रेड यूनियन को खारिज किए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस फैसले के तीन सप्ताह बाद भी राजनीतिक दलों से जुड़े कर्मचारी ट्रेड यूनियन भंग नहीं किए गए हैं। उल्टे, वे संगठित रूप में सरकार के सामने अपनी मांगों के साथ उपस्थित हुए हैं। नेपाली कांग्रेस से संबद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, यूएमएल से संबद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी से संबद्ध नेपाल राष्ट्रीय निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन एकीकृत समाजवादी से संबद्ध एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन मधेशी दलों से निकट मधेशी निजामती संगठन तथा एक स्वतंत्र संगठन सहित कुल 6 संगठनों ने शुक्रवार को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत कीं। उनकी मांग है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौतों के अनुरूप ट्रेड यूनियन अधिकारों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया जाए। संयुक्त मांगपत्र में कहा गया है कि नेपाल के संविधान की धारा 17(2)(घ) के अनुसार संघ-संगठन बनाने की स्वतंत्रता का पालन किया जाए। संविधान की धारा 34 में वर्णित श्रम संबंधी अधिकारों को लागू किया जाए। ट्रेड यूनियनों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध और हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। इन कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ट्रेड यूनियन खारिज करने के अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो सभी संगठन मिलकर संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

फर्जी नाम व आधार से साधु के भेष में निवासरत बांग्लादेशी गिरफ्तार

पौड़ी गढ़वाल। ऑपरेशन प्रहार के तहत जनपद पौड़ी पुलिस ने अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से बांग्लादेश का पुराना पासपोर्ट और सत्यनिष्ठ आर्य नाम से भारत का फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली एवं अभिसूचना इकाई लक्ष्मणझूला द्वारा संयुक्त रूप से रामझूला क्षेत्र में सघन सत्यापन एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान आसपास संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति की दी गई जानकारी विरोधाभासी एवं संदेहास्पद प्रतीत होने पर उससे गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना

वास्तविक नाम सनीउर रहमान उर्फ सत्यसाधू (39) निवासी बैसड़ी मधुखाली, फरीदपुर (बांग्लादेश) बताया। जांच में खुलासा हुआ कि वह वर्ष 2016 से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। अपनी वास्तविक पहचान छुपाने लिए उसने सत्यनिष्ठ आर्य नाम से भारतीय आधार कार्ड भी बनवा रखा था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति के दस्तावेजों को गहनता से खंगालने के साथ ही और अधिक जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान आरोपित के कब्जे बांग्लादेशी पासपोर्ट (जिसकी वैधता वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी थी), भारतीय पते पर बना आधार कार्ड, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि सामान बरामद हुआ. पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी एक दिन पूर्व ही लक्ष्मणझूला घूमने आया था, जबकि इससे पूर्व वह बंगाल, दिल्ली, गाजियाबाद एवं अन्य स्थानों पर निवास कर रहा था। आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत में अवैध निवास करने और पहचान छुपाकर रहने पर पुलिस द्वारा व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि आरोपी विषय में पुलिस, जांच एजेंसियों आदि द्वारा गहनता से जांच कर और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी को कोर्ट पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम मे वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रकाश पोखरियाल, उपनिरीक्षक हेमकांत सेमवाल, आरक्षी शूरवीर सिंह, होमगार्ड सूरजभानू के साथ ही अभिसूचना इकाई के उपनिरीक्षक सौरभ राठी मुख्य आरक्षी नरेंद्र कोठियाल,

11.30 लाख की म्यांमार मुद्रा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

आइज़ोल। मिजोरम में म्यांमार की बड़ी मात्रा में अवैध मुद्रा जब्त की गई है तथा इस संबंध में एक म्यांमार नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से की गई। असम राइफल्स के सूत्रों द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार, यह अभियान 13 अप्रैल को चाम्फाई जिले के जोखावथार क्षेत्र में चलाया गया। संयुक्त टीम ने क्रॉसिंग प्वाइंट संख्या-2 पर घात लगाकर एक म्यांमार नागरिक को पकड़ा, जिसके पास से लगभग 11.30 लाख की म्यांमार मुद्रा (म्यांमार क्यात -एमएमके) बरामद की गई। यह मुद्रा अवैध रूप से तस्करी कर लाई जा रही थी। गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त मुद्रा को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए चाम्फाई जिले के जोखावथार थाने को सौंप दिया गया है। इसी बीच, एक अन्य अभियान में असम राइफल्स और कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स ने चाम्फाई जिले के रुआनथलांग क्षेत्र में अवैध सुपारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 52 बोरी सुपारी जब्त की। जब्त सुपारी की कीमत लगभग 29.12 लाख आंकी गई है। जब्त सुपारी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स को सौंप दिया गया है।

देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य, अफवाहों से बचें: केंद्र

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की पेट्रोलियम आपूर्ति में दिक्कत के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। सरकार ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की है। साथ ही, सरकार ने यह भी बताया कि भारतीय नागरिकों और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा देश में बंदरगाहों का संचालन भी सामान्य बना हुआ है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के चलते आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बावजूद घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुचारु है। किसी भी वितरक के पास गैस खत्म होने की कोई सूचना नहीं है। प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है और हाल ही में लगभग 50 लाख से अधिक घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग का स्तर 98 प्रतिशत और प्रमाणीकरण कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93 प्रतिशत है, जबकि वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति भी काफी हद तक बहाल हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पर्याप्त है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही हैं। कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त है, जिससे आपूर्ति पर कोई दबाव नहीं है। पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। साथ ही, सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई भी तेज की है, जिसके तहत 255 वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है और 65 को निलंबित किया गया है।

विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (खाड़ी क्षेत्र) असीम आर महाजन ने कहा कि सरकार के प्रयास पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है। भारतीय मिशन और दूतावास चौबीसों घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं और जरूरतमंद नागरिकों की सहायता कर रहे हैं। समय-समय पर परामर्श जारी किए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय स्थिति, यात्रा, उड़ानों और वाणिज्य दूतावास सेवाओं से संबंधित जानकारी शामिल है।

वहीं, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि जहाजरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए समुद्री गतिविधियों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। क्षेत्र में सभी भारतीय समुद्री कर्मचारी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। अब तक 2,400 से अधिक भारतीय समुद्री कर्मचारियों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 30 को पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र से निकाला गया है। देश के सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बना हुआ है और कहीं भी भीड़भाड़ की स्थिति नहीं है।

अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा, जॉर्डन लौट रहे सैनिक

एजेंसी, दमिश्क

करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिक निकाल लिए हैं और सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकल गया। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम देश को एकजुट करने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि करीब 2000 सैनिक जॉर्डन जा रहे है।

अमेरिका ने हसाका, रुमैलान और देइर एज-जोर में मौजूद कम से कम सात बड़े ठिकाने खाली किए। आखिरी ठिकाना कसराक एयरबेस था। अब इस पर सीरियाई सेना का नियंत्रण है।

सीरियाई सरकार और SDF के बीच समझौता: इस बीच, सीरिया सरकार और SDF के बीच हुए समझौते के बाद कुर्द लड़ाकों को राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जा रहा है। हसाका और क़ामिशली जैसे शहरों में सरकारी बल तैनात हो चुके हैं और सीमाई इलाकों पर भी दमिश्क का नियंत्रण बढ़ा है। इसी साल दोनों पक्षों के बीच झड़पें भी हुई थीं, जिसके बाद मार्च में एक नया समझौता हुआ। इसके तहत SDF और कुर्द प्रशासनिक ढांचे को धीरे-धीरे राज्य में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

सीरिया ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एंटी-ISIL गठबंधन में शामिल होकर अपनी भूमिका बदली है। इससे अमेरिका के लिए सीरिया में सैन्य मौजूदगी का आधार कमजोर हुआ और अब वह क्षेत्र में अपनी रणनीति को नए सिरे से तय कर रहा है।

SDF एक कुर्द-नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसे 2015 में बनाया गया था और इसमें कुर्द, अरब और दूसरे स्थानीय समूह शामिल हैं। सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान जब सरकार कमजोर हुई, तब कुर्द लड़ाकों ने उत्तर-पूर्वी इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाद में यही SDF के रूप में मजबूत ताकत बन गया।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध विचाराधीनः भारत

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इससे जुड़ी एक याचिका की समीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में शेख हसीना के मुद्दे पर कहा कि इस संबंध में एक अनुरोध विचाराधीन है, जो चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा है। भारत इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से संवाद जारी रखेगा और हर स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव की भारत की इच्छा दोहराई है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार करने पर सहमति जताई है। वहीं, देश के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े प्रश्न पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले में ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है। इस विषय में कानूनी प्रक्रिया जारी है और भारत सरकार इस पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की स्पष्ट नीति है कि देश से भागे हुए आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संबंधित देशों के साथ समन्वय के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे, ट्रम्प बोले- शुक्रिया, भारत ने ईरान से 2,358 लोगों को निकाला

एजेंसी, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

ईरान ने लेबनान में सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने X पर पोस्ट कर बताया कि इस दौरान में सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि जहाज पहले से तय किए गए एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के समुद्री विभाग पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अराघची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने अब तक ईरान से 2,358 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इन लोगों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान पहुंचाया, जहां से उनकी भारत वापसी कराई जा रही है।

ट्रम्प का दावा- ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयारः ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड (संवर्धित) यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रम्प के दावे को गलत बताया है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं।

परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब ईरानः यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानी शुद्ध किया गया है। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों (सेंट्रीफ्यूज) के जरिए स्टेप बाय स्टेप शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को 'यूरेनियम एनरिचमेंट' कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि, यह इतना एनरिच्ड नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बन सकें। अभी 120 से 130 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम को 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। अगर यह एनरिच्डमेंट 90% तक कर लिया गया तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल, ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइप लाइन में धमाका, आठ की मौत, पांच गंभीर

एजेंसी, इस्लामाबाद

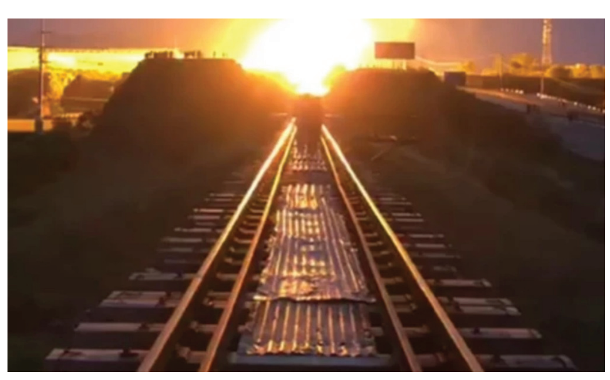

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हरिपुर में गैस पाइप लाइन में हुए धमाके में आठ लोगों की मौत हो गई। धमाके की चपेट में आए अन्य पांच की हालत गंभीर है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह सभी हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस पाइपलाइन में लगी आग में फंस गए थे। आग बुझाने के लिए आसपास से दमकल विभाग की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हरिपुर के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) वसीम अहमद ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हादसा गुरुवार को हुआ। आग में फंसे छह लोगों को बचा लिया गया। मृतकों में तीन बच्चे, दो लड़कियां, दो बुजुर्ग महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सात-आठ घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया और बचाव अभियान पूरा हो चुका है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट में कॉलोनी मोड़ के पास कोट नजीबुल्लाह में एक गैस पाइप लाइन में अचानक आग भड़क उठी। इससे पास की एक फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई। फैक्टरी के कर्मचारी तो किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन पास के रिहायशी इलाके में कई लोग फंस गए। रेस्क्यू 1122 के एक प्रवक्ता ने बताया कि बचाव और दमकल की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। आग की तीव्रता को देखते हुए मनसेहरा, एबटाबाद, मरदान और स्वाबी से सात अतिरिक्त दमकल वाहन और दमकलकर्मी बुलाए गए। इस घटना के बाद हजारा डिवीजन में गैस की सप्लाई रोक दी गई।

प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया करा रही है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस संबंध में हरिपुर के जिला पुलिस अधीक्षक शफीउल्लाह गंडापुर ने बताया कि पांच शवों को कोट नजीबुल्लाह अस्पताल और तीन को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। घायलों की हालत गंभीर है।

विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 'वस्त्र विरासत' पर केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय विरासत संस्थान (आईआईएच) ने शुक्रवार को यहां विश्व विरासत दिवस के अवसर पर एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष समारोह का आयोजन शुरू किया। यह आयोजन 17-22 अप्रैल तक चलेगा। संस्थान के अनुसार इस समारोह का उद्देश्य मानव विरासत के संरक्षण के वैश्विक संकल्प को सुदृढ़ करना है। इस बीच वंचित समुदायों के लिए 'वस्त्र विरासत' पर केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन होगा। समारोह के दौरान व्याख्यान, कार्यशालाएं और ऑनलाइन संवाद आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को (18 अप्रैल) संस्थान के सभागार में दो महत्वपूर्ण सत्र आयोजित होंगे। सुबह 11 बजे कथक नृत्यांगना डॉ. शोवना नारायण 'कथक गति में विरासतः समय और परंपरा की कथाएं' विषय पर अपनी प्रस्तुति और विचार साझा करेंगी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. संजय कुमार मंजुल 'सिंधु–सरस्वती संस्कृति के नवीन साक्ष्यः राखीगढ़ी में उत्खनन' विषय के माध्यम से इतिहास के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय विरासत संस्थान के कुलपति डॉ सच्चिदानंद जोशी करेंगे। संस्थान का संग्रहालय विज्ञान विभाग एक अनूठी पहल के तहत वंचित समुदायों के लिए विशेष कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। 'फ्रॉम कलेक्शन टू म्यूज़ियमः आवर टेक्सटाइल्स, आवर स्टोरीज़' शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को संग्रहालय और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है, जिन्हें अक्सर ऐसे अवसर नहीं मिल पाते।

स्मृति ईरानी ने सपा प्रमुख को गोरखपुर से चुनाव लड़कर जीतने की दी चुनौती

एजेंसी, वाराणसी

◆ सपा प्रमुख के 'सास बहू' वाले तंज पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने किया पलटवार

पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'सास बहू' वाले तंज पर पलटवार किया है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपनी पैतृक लोकसभा सीट से नहीं बल्कि किसी और सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। वह एक कामकाजी महिला हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पैतृक सीट (अमेठी) से चुनाव लड़कर जीत चुकी हैं। यदि अखिलेश यादव में दम है तो वह गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री शुक्रवार को चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल सभागार में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन' (सशक्त नारी, सशक्त भारत) कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू थीं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, उन्हें उनकी याद आना अच्छा है। कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना आसान होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने कभी खुद कहीं नौकरी ना की हो या फिर अपनी पहचान मेहनत से न बनाई हो। महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्टैंड पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव को धारावाहिक छोड़कर संसद के काम पर ध्यान देने और महिला सशक्तिकरण बिल का समर्थन करने की सलाह दी।

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में की 865 करोड़ की जब्ती

एजेंसी, नई दिल्ली

चुनाव आयोग की ओर से जारी सख्ती के चलते तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले अब तक कुल 865 करोड़ रुपये की नकदी एवं अवैध सामग्री की जब्ती की जा चुकी है। दोनों राज्यों में 17 अप्रैल तक कुल मिलाकर 99 करोड़ रुपये नकद, 32 लाख लीटर 84 करोड़ रुपये की शराब, 174 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 159 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 350 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं।

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मतदान को हिंसा, भय और लालच से मुक्त रखने के लिए कई उपाय किए गये हैं । इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है और शिकायतों को त्वरित निपटान किया जा रहा है। आयोग की ओर से 5011 फ्लाइंग स्क्वायड टीम तैनात की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 शामिल हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों में 5,363 निरीक्षण टीम तैनात की गई है।

आयोग के अनुसार 26 फरवरी को चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद 17 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती की गई।

पश्चिम बंगाल में 21 करोड़ रुपये नकद, 31 लाख लीटर शराब (81 करोड़ रुपये मूल्य), 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 54 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं तथा 172 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गईं। कुल जब्ती 427 करोड़ रुपये रही। वहीं तमिलनाडु में 78 करोड़ रुपये नकद, 97 हजार लीटर शराब (3 करोड़ रुपये मूल्य), 74 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 105 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं तथा 178 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं जब्त की गईं। कुल जब्ती 438 करोड़ रुपये रही।

विशेष संसद सत्र 16-18 अप्रैल 2026- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बनाम प्रॉक्सी राजनीति व नेतृत्व,आपराधिक दखल,बैक-डोर कंट्रोल, राजनीतिक ढाल बनाकर दुरुपयोग की चुनौती-कठोर सजा की धाराएं जोड़ने की जरूरत-एक समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर- भेदभाव की गारंटी देते हैं,साथ ही अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है- समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों क़ा संतुलन आवश्यक

» विशेष संसद सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023- प्रॉक्सी पॉलिटिक्स,राजनीतिक ढाल, आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल रोकने कठोर सजा का प्रावधान ज़रूरी ताकि वास्तविक सशक्तिकरण हों -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक संतुलन स्थापित करना है। यह कदम केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ भी उभरकर सामने आई हैंविशेषकर प्रॉक्सी नेतृत्व या बैक-डोर कंट्रोल का खतरा, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर वास्तविक सत्ता उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में होती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह समस्या भारत तक सीमित नहीं है; विश्व के कई लोकतंत्रों में महिला आरक्षण या कोटा लागू होने के बाद इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने आई हैंइसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस अधिनियम के निहितार्थों, संभावित जोखिमों और सुधारात्मक उपायों का गहन विश्लेषण करें।ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव हमारे विज़न 2047 के लिए सटीक रूप से मील का पत्थर साबित हो। साथियों बात अगर हम मुद्दों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यह हैकि क्या महिला जनप्रतिनिधियों का पारिवारिक पुरुषों द्वारा नियंत्रित होना मतदाताओं के विश्वास का हनन है?लोकतंत्र की मूल आत्माप्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जब मतदाता किसी महिला को उसकी ईमानदार छवि, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनते हैं, तब वे अपेक्षा करते हैं कि वही महिला नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी। लेकिन यदि वास्तविक निर्णय उसके पति या परिवार के

पुरुष सदस्य लेते हैं, तो यह न केवल मतदाता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कमजोर करता है। भारत के कई राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच पति की प्रवृत्ति एक स्थापित वास्तविकता बन चुकी है, जहाँ निर्वाचित महिला केवल नाममात्र की मुखिया होती है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में रहती है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर देती है और उन्हें मात्र एक तुच्छ राजनीतिक औजार बना देती है। साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद बैक-डोर नेतृत्व की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,तोराजनीतिक दल और प्रभावशाली पुरुष नेता अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से ही स्थानीय निकायों में देखी जा चुकी है और यह संभावना है कि यह अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में महिला कोटा लागू होने के बाद प्रारंभिक वर्षों में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा,जहाँ महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि थीं। हालांकि समय के साथ, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ संस्थागत और सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं।

साथियों तीसरा बिंदु यह है कि क्या अयोग्य या अक्षम पुरुष नेता, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते, महिलाओं को आगे कर बैक-डोर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे? यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पहले से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ऐसे में, यदि किसी पुरुष नेता पर कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध है, तो वह अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का उपयोग कर सकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, बल्कि योग्य और स्वतंत्र महिला नेताओं के उभरने में भी बाधा डालता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अति अति सतर्कता व पारदर्शिता से ही संभव है। साथियों चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कैदियों की संख्या पिछले दो दशकों में 162 प्रतिशत बढ़ी है, जो पुरुष कैदियों की वृद्धि दर (77 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। यह असंतुलन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या उन्हें आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? कई मामलों में यह पाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे अपराधों में महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें कम संदेहास्पद माना जाता है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसे राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। यदि आपराधिक तत्व महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगें, तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ अवैध प्रवास और तस्करी की समस्या अधिक है, यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। साथियों पाँचवाँ मुद्दा आरक्षण के व्यावहारिक प्रभाव से जुड़ा है। यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,और वहाँ पर्याप्त योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संभावना है कि अपेक्षाकृत कम सक्षम उम्मीदवार ही निर्वाचित हो जाएँ। यह स्थिति मतदाताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण हो सकती है,क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसे व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वंचित वर्ग को अवसर दिया जाता है, तो प्रारंभिक वर्षों में चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ वह वर्ग अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए, इस समस्या का समाधान आरक्षण को

समाप्त करना नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण और राजनीतिक सहभागिता के अवसर बढ़ाना है। साथियों छठा और अंतिम बिंदु संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिला आरक्षण के कारण पुरुषों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता के अधिकार, का उल्लंघन न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति भी देता है। इसलिए, महिला आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते कि यह समान अवसर और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यहाँ संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, न कि नए प्रकार के असंतुलन पैदा करे। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ ठोस दंडात्मक व सुधारात्मक उपाय जोड़े जाएँ। साथियों सबसे पहले, प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जिनमें आर्थिक और आपराधिक दंड शामिल हों। यदि यह साबित होता है कि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की है और वास्तविक निर्णय कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है, तो उस पर और संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, महिला प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम नेता बन सकें। तीसरा, राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करना होगा और महिलाओं को केवल टोकन उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक नेता के रूप में आगे बढ़ाना होगा। चौथा, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; उन्हें ऐसे मामलों को उजागर करना चाहिए जहाँ महिलाओं का दुरुपयोग किया जा रहा हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा गया है कि महिला आरक्षण तभी सफल होता है जब उसे व्यापक सामाजिक और संस्थागत सुधारों के साथ जोड़ा जाए। रवांडा, नॉर्वे और फ्रांस जैसे देशों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की वास्तविक भागीदारी भी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति का स्तर उच्च है। भारत को भी इस दिशा में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अंततः, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम "संख्यात्मक प्रतिनिधित्व" को "वास्तविक सशक्तिकरण" में कैसे बदलते हैं। यदि हम प्रॉक्सी नेतृत्व, आपराधिक दखल अंदाजी और संस्थागत कमजोरियों को दूर करने में सफल होते हैं, तो यह अधिनियम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है। अन्यथा, यह केवल एक कागजी सुधार बनकर रहजाएगा जो अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहेगा। इसलिए, समय की मांग है कि हम इस कानून को केवल एक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखें और इसे सफल बनाने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर और ठोस प्रयास करें।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

विश्लेषण- क्या 'सम्राट' संभाल पाएंगे नीतीश के भरोसे की विरासत?

लेखक- योगेश कुमार गोयल

बिहार की राजनीति में सत्ता का शिखर छूना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उस शिखर पर टिके रहकर अपनी सर्वमान्यता सिद्ध करना। सम्राट चौधरी का बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उदय राज्य के सियासी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस 'बड़े भाई' की भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार की उस लंबी और गहरी छाया से बाहर निकल पाएंगे, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है? यही वह कसौटी है, जिस पर अब सम्राट चौधरी को परखा जाएगा। सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़ा नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूंक सकता था बल्कि राजद के 'माई' (एमवाई) समीकरण के सामने एनडीए के 'लव-कुश' समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने हैं, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बढ़ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए हिमालयी चुनौतियों जैसी हैं। नीतीश कुमार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वह बिहार के लिए एक 'इंस्टीट्यूशन' बन चुके थे। उनके 20 वर्षों के शासनकाल ने राज्य में सुशासन की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़कें, बिजली और शराबबंदी जैसे मुद्दे हर घर से जुड़े थे। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे स्वयं को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करते हैं या एक ऐसी नई पहचान गढ़ते हैं, जो नीतीश के 'विकास' और भाजपा की 'वैचारिक प्रखरता' का संगम हो। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य नेता बनना सम्राट चौधरी के लिए रातों-रात संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग, चाहे वह महादलित हो, अति पिछड़ा हो या आधी आबादी (महिलाएं) हो, में गहराई तक थी। सम्राट चौधरी के पास फिलहाल एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है लेकिन उन्हें अपनी 'आक्रामक छवि' को अब 'प्रशासकीय संयम' में बदलना होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अब उनके हर फैसले की तुलना नीतीश कुमार के मानकों से की जाएगी। क्या वह उसी सहजता से महादलितों और अति पिछड़ों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या वह शराबबंदी जैसी पेचीदा नीतियों को लेकर जनता के बीच अपना स्पष्ट नजरिया रख पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं।

विश्व धरोहर दिवसः सभ्यता की अमूल्य धरोहरों को बचाने का संकल्प

लेखक- सुनील कुमार महला

प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे तथा आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस (इंटरनेशनल डे फोर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स) कहा जाता है। यह दिवस मानवता की साझा सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।वास्तव में, विश्व धरोहर स्थल (वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स) वे स्थान हैं जिन्हें मानवता के लिए उनके असाधारण सार्वभौमिक महत्व के आधार पर मान्यता दी जाती है और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। इन स्थलों का संरक्षण यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 के अंतर्गत किया जाता है, जिसे यूनेस्को सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता माना जाता है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्वभर के ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, पुरातात्विक अवशेषों, प्राकृतिक संपदाओं तथा मानव सभ्यता से जुड़ी अमूल्य विरासतों के संरक्षण के प्रति जनचेतना उत्पन्न करना है। वास्तव में धरोहर केवल पत्थरों से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा, कला, ज्ञान, संघर्ष, इतिहास और सामूहिक पहचान की जीवंत प्रतीक हैं। उल्लेखनीय है कि इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा ट्यूनीशिया में आयोजित बैठक में हुई, जहाँ 18 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद वर्ष 1983 में यूनेस्को की 22वीं महासभा ने इसे औपचारिक मान्यता प्रदान की। तभी से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को यह दिवस विश्वभर में मनाया जाता है। विश्व धरोहर स्थल विशेष स्थान, भवन, दुर्ग, नगर, वन, पर्वत, झील, मरुस्थल या प्राकृतिक क्षेत्र हो सकते हैं, जिन्हें मानवता के लिए विशिष्ट महत्व का माना जाता है। किसी स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल करने से पूर्व यूनेस्को उसे कठोर मानकों पर परखता है। वर्तमान में 10 चयन मानदंड निर्धारित हैं, जिनमें से कम से कम एक को पूरा करना आवश्यक है। इनमें ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक प्रभाव, प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता तथा वैज्ञानिक महत्त्व जैसे पहलू सम्मिलित हैं।विश्व धरोहर मुख्यतः तीन प्रकार की होती है- पहली, सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें स्मारक, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, मूर्तियाँ, प्राचीन नगर, स्थापत्य कला, भाषा, संगीत, नृत्य और परंपराएँ शामिल हैं। दूसरी, प्राकृतिक धरोहर, जिसमें पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वन, वन्यजीव, जैव विविधता और अद्वितीय प्राकृतिक परिदृश्य आते हैं तथा तीसरी, मिश्रित धरोहर, जिनमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों विशेषताएँ विद्यमान होती हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यूनेस्को केवल स्थायी संरचनाओं या प्राकृतिक स्थलों को ही नहीं, बल्कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भी मान्यता देता है। भारत की योग परंपरा और कुंभ मेला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व स्तर पर सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला देश इटली है, जिसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत भी विश्व धरोहर स्थलों की दृष्टि से अग्रणी देशों में सम्मिलित है। यूनेस्को एक विशेष सूची वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर भी संचालित करता है, जिसमें उन स्थलों को शामिल किया जाता है जो युद्ध, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, अतिक्रमण, अत्यधिक पर्यटन, जलवायु परिवर्तन या उपेक्षा के कारण संकट में हों। यदि कोई स्थल संरक्षण मानकों का पालन न करे या उसका मूल स्वरूप गंभीर रूप से बदल जाए, तो उसे सूची से हटाया भी जा सकता है। उदाहरणस्वरूप ओमान का अरेबियन ओरिक्स अभयारण्य तथा जर्मनी की ड्रेसडेन एल्बे घाटी को सूची से हटाया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2024 तक विश्वभर के 196 देशों में लगभग 1,223 विश्व धरोहर स्थल थे, जिनमें 952 सांस्कृतिक, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित स्थल शामिल हैं। भारत जैसे प्राचीन और बहुसांस्कृतिक देश में इस दिवस का विशेष महत्व है। अप्रैल 2025 तक भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल (34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 2 मिश्रित) तथा 62 स्थल संभावित सूची में सम्मिलित थे। भारत के प्रमुख धरोहर स्थलों में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, अजंता-एलोरा गुफाएँ, एलीफेंटा गुफाएँ, खजुराहो समूह, सांची स्तूप, महाबोधि मंदिर, हम्पी, महाबलीपुरम, जंतर-मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क सूर्य मंदिर, नालंदा, भीमबेटका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट तथा कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। राजस्थान धरोहर संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ जयपुर शहर, जंतर-मंतर जयपुर, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर किला, गागरोन दुर्ग तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। वर्ष 2021 में भारत के रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) तथा धोलावीरा (गुजरात) को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत की संख्या में वृद्धि हुई।विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष एक विशेष थीम घोषित की जाती है।वर्ष 2025 की थीम थी- आपदाओं और संघर्षों से विरासत खतरे मेंः आइसीओएमओएस के 60 वर्षों के अनुभवों से तैयारी और सीख। तथा वर्ष 2026 की थीम है-संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। रखी गई है।इसका आशय यह है कि युद्ध, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के समय केवल भवनों और स्मारकों की ही नहीं, बल्कि जीवित विरासतों- जैसे लोक परंपराएँ, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक पहचान और समुदाय आधारित परंपराएँ की भी त्वरित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान समय में बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवैध निर्माण, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ और लापरवाही अनेक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट बनकर खड़े हैं। इसलिए इनका संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। धरोहरों से हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है और पर्यटन उद्योग को नई दिशा मिलती है। भारत सरकार ने भी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अनेक महत्त्वपूर्ण पहलें की हैं। विदेशों में पहुँचे प्राचीन पुरावशेषों की वापसी के प्रयास तेज किए गए हैं, और वर्ष 1976 से अब तक लगभग 655 पुरावशेष भारत वापस लाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक-स्थान जैसी कृतियों को यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति के एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक सम्मान मिला। यह अच्छी बात है कि वर्ष 2017 में प्रारंभ हेरिटेज एडॉप्ट कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं को सीएसआर फंडिंग के जरिए विरासत स्थलों के संरक्षण और विकास में भागीदारी का अवसर दिया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन के अंतर्गत 12.3 लाख से अधिक पुरावशेषों तथा 11,400 विरासत स्थलों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

कानून की ओट में, सम्मान का क्षरण

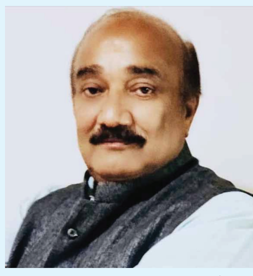

लेखक- पं.नरेश शर्मा

प्रारंभ से ही सम्मान, संवेदना एवं अनुशासन पुलिस की मूल पहचान है। गणवेश केवल अधिकार नहीं अपितु मर्यादा, अनुशासन, सुरक्षा एवं सेवा का भी प्रतीक है। म.प्र.पुलिस का तो ध्येय वाक्य ही देशभक्ति जनसेवा है। यह अवधारणा राष्ट्र के प्रति समर्पण, नागरिक हित, समाज की सुरक्षा एवम् कर्तव्यनिष्ठा की द्योतक है। यदि वर्दी के भीतर सम्मान टूटता है तो समाज में विश्वास क्षीण होता है। विगत 07 अप्रैल 2026 की थाना मडला जिला पन्ना द्वारा सेवा निवृत अस्वस्थ एवं वयोवृद्ध पुलिस अधिकारी को ड्राइवर के बाजू की सीट पर बगैर सीट बेल्ट के बैठे होने की साधारण सी मानवीय भूल के कारण पत्नि सहित घोर अपमानित कर गिरफ्तार करना उनकी संपूर्ण सेवा की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। इसे केवल घटना नहीं अपितु एक चेतावनी के रूप में लेने एवम् पुलिस व्यवस्था के भीतर अनुशासन प्रशिक्षण व भारतीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर समझना होगा। घटना से अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि -- क्या पुलिस में अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती किया जा रहा है? क्या उनका प्रशिक्षण युक्तियुक्त नहीं हो रहा है? पुलिस में आंतरिक अनुशासन का सर्वोपरि होना सिखलाया नहीं जा रहा है? वरिष्टों के प्रति सम्मान का ह्रास न हो, यह परंपरा पुलिस की रीढ़ है। विशेष आयु एवं अनुभव के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है, क्या यह पाठ प्रशिक्षण में या जिला स्तर के सेमिनारों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस में अनुशासन का संकट गहरा रहा है। कुछेक रक्षक मर्यादा भूल रहे हैं, जिनके कारण आंतरिक अनुशासन को चुनौती मिल रही है। यह चिंताजनक संकेत है। यह वर्दी का गौरव नहीं अपितु अहंकार का प्रतीक है। यह कहते हुए अत्यन्त पीड़ा हो रही है कि सम्मान खोती वर्दी पर से समाज का विश्वास टूटा जा रहा है। प्रश्न केवल थाने के समक्ष उपस्थित होकर कानून की ओट में वाहन चेकिंग कर रहे अनाधिकृत पुलिस के आरक्षक स्तर के कर्मचारियों का ही नहीं है अपितु विवाद बढ़ता देख घटना स्थल पर आई महिला थाना प्रभारी ने भी उदण्डता कर रहे अनुशासनहीन अधीनस्थों का न केवल समर्थन किया अपितु स्वयं भी पर्याप्त सम्मानजनक व्यवहार न कर दीर्घ कालीन पुलिस सेवा से निवृत अस्वस्थ दम्पत्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 132, 351, 221, 3(5) सहपठित धारा 27, 30 आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत कर बिना किसी अनुसंधान के, गिरफ्तारी के समस्त नियमों एवं विधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, अवैधानिक रूप से, कारण बताये बिना उन्हें गिरफ्तार कर लिया एवम् साशय विलम्ब कर सायं 05.30 बजे जेल भेजने की पूर्ण मंशा से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संयोगवश न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार कर ली गई। ग्वालियर जा रहे दंपत्ति की कार भी जप्त कर ली गई जिसे दो दिनों बाद न्यायालय के आदेश से छोड़ा गया। अत्यंत दुखद एवम् आश्चर्य का विषय यह है कि वरिष्ठ सम्माननीय वृद्धा तो मात्र शालीनता पूर्वक उभय पक्षों को समझा रही थी। उनका यह प्रयास आपराधिक कैसे हो गया? उनकी 40 वर्ष पुरानी लाइसेंस युक्त बंदूक भी जप्त कर ली गई। प्रकरण में अधिरोपित आरोपों में 07 वर्ष से अधिक कारावास के दण्ड का प्रावधान नहीं है व प्रकरण प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारण योग्य हैं। दृष्टांत प्रकरण अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (2014) में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में इस प्रकरण में गिरफ्तारी की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत करते समय अभियुक्तों की उपस्थिति मात्र सूचना पत्र देकर सुनिश्चित करना पर्याप्त होता है किन्तु पुलिस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना ही नहीं की गई अपितु संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए एक वरिष्ठ दम्पत्ति के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का भी अतिक्रमण किया है। इसमें पुलिस अधीक्षक की असंवेदनशीलता एवं मौन स्वीकृति भी स्पष्ट प्रतीत होती है अतः प्रकरण का स्वतंत्र इकाई से अनुसंधान नितान्त अवश्यक है व दुर्भावनापूर्वक मिथ्या अंकित प्रथम सूचना पत्र का निरस्तीकरण वांछनीय है। एक समय था ! बहुत पुराना नहीं, कुछ ही साल पहले का... हमारा जमाना। यद्यपि यह स्वीकार्य तथ्य है कि पश्चात्वर्ती को पूर्ववर्ती से निंदा का सामना करना पड़ता है किंतु मेरी निसंकोच स्वीकारोक्ति है कि हमसे पहले का समय और भी अच्छा था। वरिष्ठों के अनुसरण से ही हमारे द्वारा थानों में शासकीय विभागों के वर्गीकरण युक्त पेंशनधारियों की पंजी संधारित कर रखी जाती थी एवम् समय समय पर उनसे विमर्श कर उनके अनुभवों का लाभ भी प्राप्त किया जाता था। हम तो एक पखवाड़े के एक निश्चित दिन को सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर उनके साथ चाय पीते व समस्याओं के निराकरण पर मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे।

आईसीसी ने जारी किया महिला टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी का शेड्यूल

टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा

नईदिल्ली (एजेंसी)। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रवांडा में आयोजित होने वाली पहली महिला टी-20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्राफी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट 19 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा। इसका आयोजन किगाली शहर में होगा, जहां गहांगा क्रिकेट स्टेडियम के दो सटे मैदानों पर मैच खेले जाएंगे।

कार्यक्रम के अनुसार, पांच टीमों के इस टूर्नामेंट के पहले दिन इटली का मुकाबला मेजबान रवांडा से होगा, जबकि नेपाल का सामना अमेरिका से होगा। वानुअतु को पहले दिन बाई मिली है और 19 अप्रैल को वह रवांडा से भिड़ेगी। यह टूर्नामेंट आईसीसी द्वारा शुरू किया गया एक नया आयोजन है, जिसका उद्देश्य सहयोगी सदस्य टीमों को अधिक अवसर प्रदान करना है। यह इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के साथ जुड़ता है, जिसका पहला संस्करण पिछले नवंबर में हुआ था, और यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अवसरों का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है।

इस प्रतियोगिता में आईसीसी के पांचों क्षेत्रों की शीर्ष रैंकिंग वाली टीमें भाग ले रही हैं, जो इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं। सभी पांचों प्रतिभागी टीमों ने 2025 के क्षेत्रीय महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में अपने प्रदर्शन के आधार पर टूर्नामेंट में जगह बनाई है। डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट 2 मई तक चलेगा और इसका उद्देश्य लगातार उच्च गुणवत्ता वाला मैच अनुभव प्रदान करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट को मजबूत करने और उभरती टीमों को मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के आईसीसी के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

यह आयोजन महिला टी20 वर्ल्ड कप के विस्तार के अनुरूप भी है, जिसमें 2026 तक 12 टीमें शामिल हो जाएंगी और 2030 तक 16 टीमों तक विस्तार करने की योजना पहले ही पुष्ट हो चुकी है। नेपाल और अमेरिका इस टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने इस वर्ष की शुरुआत में हुए नवीनतम ग्लोबल क्वालीफायर में भाग लिया था। आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में 21वें स्थान पर काबिज नेपाल, प्रतियोगिता में सबसे उच्च रैंकिंग वाली टीम है। वहीं, वर्तमान में 30वें स्थान पर काबिज वानुअतु ने पिछले साल फिजी में आयोजित ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान पक्का किया, जहां उन्होंने 20वें स्थान पर काबिज इंडोनेशिया को हराया था।

18 अप्रैल
रवांडा बनाम इटली
नेपाल बनाम अमेरिका

19 अप्रैल
रवांडा बनाम वानुअतु
इटली बनाम नेपाल

21 अप्रैल
रवांडा बनाम अमेरिका
वानुआतु बनाम इटली

22 अप्रैल
रवांडा बनाम नेपाल
अमेरिका बनाम वानुअतु

24 अप्रैल
नेपाल बनाम वानुअतु
इटली बनाम अमेरिका

26 अप्रैल
रवांडा बनाम वानुअतु
अमेरिका बनाम नेपाल

27 अप्रैल
रवांडा बनाम इटली
अमेरिका बनाम वानुअतु

28 अप्रैल
रवांडा बनाम नेपाल
इटली बनाम वानुअतु

3 अप्रैल
इटली बनाम अमेरिका
नेपाल बनाम वानुअतु

1 मई
रवांडा बनाम अमेरिका
इटली बनाम नेपाल

अगले हफ्ते धोनी आईपीएल में वापसी कर सकते हैं

वानखेड़े या चेपॉक में खेल सकते हैं; अभी काफ इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं

चेन्नई (एजेंसी)। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले हफ्ते आईपीएल में वापसी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीम सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि उनकी चोट में तेजी से सुधार हो रहा है और वह आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। धोनी को आईपीएल शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान पिंडली में खिंचाव आ गया था। इसी वजह से वह टूर्नामेंट के शुरुआती तीन हफ्तों में नहीं खेल पाए। अब उनकी वापसी को लेकर कयास तेज हो गए हैं। संभावना है कि धोनी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह 26 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेलते नजर आ सकते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे – चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। हालांकि, इस मैच में धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे। टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। सीएसके के सूत्रों ने कहा, धोनी अभी रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम उनकी फिटनेस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्हें पूरी तरह फिट होने का समय दिया जा रहा है।

प्रैक्टिस सेशन में की लंबी बल्लेबाजी, रेंज हिटिंग पर फोकस – भले ही धोनी मैच नहीं खेल रहे हैं.

डी कॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जड़ा धमाकेदार शतक, टूट गया धोनी का रिकॉर्ड

आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

31 – केएल राहुल
25 – क्विंटन डी कॉक*
24 – एमएस धोनी
21 – दिनेश कार्तिक
21 – ऋषभ पंत
20 – संजू सैमसन

मुंबई (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के ओपनर क्विंटन डी कॉक ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. आईपीएल 2026 में पहला मैच खेल रहे डी कॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शतक जड़ा. यह इस सीजन का दूसरा शतक और डी कॉक का तीसरा शतक है. वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए डी कॉक का यह पहला शतक है। डी कॉक ने 53 बॉल में अपना शतक पूरा किया. यह उनका तीसरा आईपीएल शतक है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए यह कारनामा किया था. डी कॉक ने 60 बॉल में 112 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में आठ चौके और सात छक्के शामिल थे. 2014 में मोहाली में लेंडल सिमंस के 100* (61) के बाद आईपीएल में पीबीकेएस के खिलाफ मुंबई के किसी बल्लेबाज की तरफ से बनाया गया यह दूसरा शतक है डी कॉक ने नमन धीर (50) के साथ 122 रन की साझेदारी की, जिससे मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 195 रन बनाए ।

आईपीएल में डी कॉक का शतक

- 108 (51), डीडी बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016
- 140* (70), एलएसजी बनाम केकेआर डीबाय पाटिल , 2022
- 101* (53), मुंबई बनाम पीबीकेएस बानखेड़े , 2026

डी कॉक ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

डी कॉक ने इस पारी के साथ एमएस धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला. वह आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने 25 बार यह कारनामा किया है. धोनी ने बतौर विकेटकीपर आईपीएल में 24 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है।

अर्शदीप सिंह का मुंबई के खिलाफ डबल-स्ट्राइक, लगाई शानदार 'सेंचुरी'

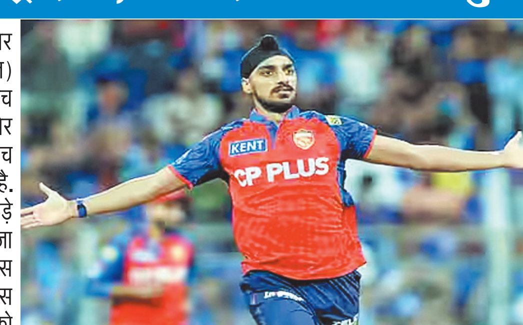

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का 24वां मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर मुंबई को बल्लेबाजी का न्योता दिया. मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अर्शदीप सिंह ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया. अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने मुंबई को लगातार गेंदों पर दो झटके दे दिए. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए।

- **आईपीएल में 100 विकेट पूरे किए** – मुंबई की पारी के तीसरे ओवर में बाएं हाथ के इस पेसर ने पहले रियान रिकल्टन का विकेट लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने ऑन साइड की गेंद पर हवाई फ्लिक किया. यह गेंद बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन रिकल्टन इसका फायदा नहीं उठा पाए. गेंद टप्पा खाने के बाद उनके पैड पर आई. रिकल्टन का शॉट हालांकि सीधा फील्डर के हाथों में गया. डीप स्क्वेअर लेग पर खड़े शशांक सिंह ने आसान सा कैच लपका.
- **हार्दिक पंड्या के आईपीएल में 150 सिक्स पूरे** – 18वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पंड्या ने छक्का लगाकर आईपीएल में अपने 150 सिक्स पूरे किए। मार्को यानसन की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर हार्दिक ने सामने की ओर शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार गई। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पंड्या आउट हो गए।

व्यापार

कच्चा तेल 130 पहुंचा, तब भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, एस एंड पी रेटिंग्स ने माना इकॉनमी का लोहा

नई दिल्ली, एजेंसी। रेटिंग एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया के संकट के बीच अगर इस वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल भी पहुंच जाती है, तो भी भारत 6.3 प्रतिशत की रफ्तार से तरक्की करेगा। एजेंसी ने यह भी साफ किया कि तेल की कीमतों में उछाल से पड़ने वाले बोझ का भारत की 'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग' (देश की साख) पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारत लंबे समय में अपने राजकोषीय घाटे को कम करने और सरकारी खजाने को मजबूत बनाए रखने के लिए राजनीतिक रूप से पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डायरेक्टर (सॉवरेन रेटिंग्स) यी फर्न फुआ ने एक वेबिनार में बताया कि अगर हम सामान्य हालात मानकर चलें और कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल रहता है, तो भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि

अगर तेल की औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल तक चली जाती है, तब भी भारत की विकास दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। यह दर तब भी दुनिया की बड़ी इकॉनमीज में सबसे ज्यादा होगी। फुआ ने कहा, ''दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में यह आंकड़ा अभी भी बहुत मजबूत है। वैकल्पिक परिदृश्य में भी, अगर मैं कहूं कि औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो भी हम 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देख रहे हैं। ऐसे में भी भारत की वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।''

एसएंडपी ने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान, जिससे ईंधन या उर्वरक जैसे संबंधित उत्पादों की कमी होती है, एक जोखिम होगा। दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में यह आंकड़ा अभी भी बहुत मजबूत है। वैकल्पिक परिदृश्य में भी, अगर मैं कहूं कि औसत कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो भी हम 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देख रहे हैं। ऐसे में भी भारत की वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। यी फर्न फुआ, एस एंड पी के डायरेक्टर (सॉवरेन रेटिंग्स) ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई थी और यह 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। यह चार साल में इसका उच्चतम स्तर है। इसकी वजह यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवाजाही बंद हो गई है। यहां से दुनिया का 20 फीसदी तेल और करीब एक तिहाई गैस गुजरती है।

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत देने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। मामले से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक, यह योजना इसलिए बनाई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे हालात में आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। यह प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। दाल, प्याज, आलू और टमाटर जैसी जरूरी चीजों के लिए स्थिरता कोष साल 2015 में शुरू किया गया था। जब इन चीजों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो सरकार इस फंड से सामान खरीदकर बाजार में बेचती है, जिससे कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। अब सरकार इसी तरह का फंड पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए बनाना चाहती है। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई है। सरकार इस फंड के जरिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का एक तय मात्रा में भंडार (रिजर्व) तैयार करेगी। इसके लिए तेल रिफाइनरी कंपनियों के साथ समझौते किए जाएंगे। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अचानक बढ़ेंगी या सप्लाई बाधित होगी।

भारत पर रखिए नजर, अमेरिका हो या ईरान सभी से रिश्ते, कियोसाकी ने समझाया नई दिल्ली का किरदार

नई दिल्ली, एजेंसी। जाने-माने लेखक और दिग्गज निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने बदलते भू-राजनीतिक हालातों में भारत के किरदार को समझाया है। उन्होंने भारत के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए दुनिया से इस पर करीब से नजर रखने की अपील की है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने बताया है कि आखिर ईरान में जारी संघर्ष के बीच नई दिल्ली ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्यों लगातार केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल के बाद उन्होंने अपनी राय जाहिर की। कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें कियोसाकी ने कहा कि ट्रंप-मोदी के बीच यह बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली। इस साल इन दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बातचीत थी। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद से यह दूसरी थी। उन्होंने आगे कहा कि यह बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई। ट्रंप के शब्दों को कोट करते हुए बताया, 'मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं।' कियोसाकी ने ईरान और इजरायल दोनों में अपनी आर्थिक माजूदगी के जरिये भारत की अद्वितीय स्थिति को हाईलाइट किया। ईरान और

इजरायल दोनों ही इस संघर्ष में आमने-सामने हैं। ईरान में भारत ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह के 'शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल' को ऑपरेट करता है। इस परियोजना में 55 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। इसके संचालन के लिए 10 साल का समझौता है। यह बंदरगाह सेंट्रल एशिया तक भारत की व्यापक कनेक्टिविटी योजनाओं का भी एक हिस्सा है। इजरायल में अडानी ग्रुप ने 1.2 अरब डॉलर में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। भूमध्य सागर पर स्थित यह बंदरगाह पूरी तरह से चालू है। इस क्षेत्र में इसे एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। कियोसाकी के अनुसार, भारत का प्रभाव इस बात से दिखता है कि वह इस संघर्ष में शामिल लगभग सभी पक्षों के साथ कामकाजी संबंध बनाए रखने में सक्षम है। इनमें अमेरिका, ईरान, इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, रूस और चीन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संकट के शुरुआती 48 घंटों में मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर जोरदार सक्रियता दिखाई। उन्होंने पश्चिम एशिया के कई नेताओं से बातचीत की। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से और बाद में ट्रंप से भी बातचीत की। कियोसाकी ने मोदी और पेजेश्कियन के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया। इसमें भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों की दोबारा पुष्टि की थी। उन्होंने बताया कि तेहरान ने भारत के 'संतुलित और रचनात्मक रुख' की सराहना की। नई दिल्ली को ब्रिक्स में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। यह वैश्विक स्तर पर समीकरणों में आ रहे बदलावों के इस दौर में भारत की कूटनीतिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत बनाता है। व्यापक जुड़ाव के बावजूद भारत ने सार्वजनिक तौर पर एक नपा-तुला रुख बनाए रखा है। कियोसाकी ने गौर किया कि नई दिल्ली ने शांति और बातचीत का आह्वान किया है।

मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने एशिया के सबसे बड़े रईस

नई दिल्ली, एजेंसी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। उन्होंने हमवतन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ अब 92.6 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 8.10 अरब डॉलर की तेजी आई है। इसके साथ ही वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ अंबानी की नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 16.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट रही। सेंसेक्स 123 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी रही। इससे अडानी की नेटवर्थ में 3.56 अरब डॉलर की तेजी आई। वहीं अंबानी की नेटवर्थ 76.7 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। रिलायंस का शेयर कल लगभग सपाट बंद हुआ था। अंबानी एशिया में दूसरे और दुनिया में 20वें नंबर पर हैं। इस साल दुनिया के टॉप 20 अमीरों में से 7 की नेटवर्थ में गिरावट आई है। फ्रांसीसी बिजनसमैन बर्नार्ड आरनॉल्ट ने सबसे ज्यादा 44 अरब डॉलर गंवाए हैं। इस लिस्ट में आरनॉल्ट के अलावा स्टीव बालमर, ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स, जाने माने निवेशक वॉरेन बफे, स्पेन के दिग्गज एमेनशियो ओर्टेगा और मुकेश अंबानी शामिल हैं। एलन मस्क 656 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। इस

साल उनकी नेटवर्थ में 36.7 अरब डॉलर की तेजी आई है। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज 286 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ऐमजॉन के जेफ बेजोस (269 अरब), सर्गेई ब्रिन (266 अरब), मार्क जकरबर्ग (239 अरब), लैरी एलिसन (230 अरब), माइकल डेल (.170 अरब), जेंसन हुआंग (.164 अरब), बर्नार्ड आरनॉल्ट (.164 अरब) और जिम वॉल्टन (.150 अरब) भी टॉप 10 में शामिल हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)